THE BUDGET (GENERAL), 2014-15

AND

THE APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2014 *(Contd.)*

श्री भुपेन्द्र यादव (राजस्थान) : माननीय उपसभापति महोदय, अभी इस बजट के संबंध में हमारे सम्माननीय सदस्य श्री आनन्द शर्मा जी विषय रख रहे थे, तो उन्होंने विषय को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि हमारे सम्माननीय वित्त मंत्री के लिए वे एक संकट भारी कुर्सी छोड़कर गए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संकट को बड़ी सहजता से स्वीकार किया है और बड़ी कुशलता के साथ इन संकटों से निपटने के लिए देश के लिए एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। आनन्द शर्मा जी सही कह रहे थे कि जो देश का आर्थिक बजट होता है, वह आपके दर्शन और नीतियों पर आधारित होता है और किसी भी सरकार का बजट उसकी आर्थिक नीतियों को प्रस्तुत करता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट हमारे सामने रखा है, उस बजट की अगर आर्थिक नीतियां और दर्शन हैं, तो उसकी आर्थिक नीतियों और दर्शन के दो भाग हैं कि देश का आर्थिक विकास सतत् रूप से जारी रहे और उसके साथ हमारे देश का जो मानव सूचकांक है, मानव कल्याण है, वह भी आगे बढ़े और दोनों को मिलाकर देश को विकास की नई प्रेरणा मिले। आनन्द शर्मा जी कह रहे थे कि पिछले दो वर्षों में जो विकास की गति कम हुई है, उसका एक कारण वैश्विक संकट है, लेकिन उसका एकमात्र कारण वैश्विक संकट नहीं था। अगर आप सरकार के द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा-पत्र का अध्ययन करेंगे और अगर पिछले वर्षों की पॉलिसीज का भी अध्ययन करेंगे, तो वैश्विक संकट अपनी जगह था, लेकिन देश के पिछड़ने का कारण परियोजना क्षेत्रों के क्रियान्वयन में ज्यादा समय लगना था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform the hon. Members that for some time the hon. Finance Minister may be away. He has gone with my permission. I have permitted him. The MoS will be here.

(THE VICE-CHAIRMAN, SHRI TIRUCHI SIVA, in the Chair)

श्री भुपेन्द्र यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस वैश्विक संकट के साथ-साथ जो पिछले दस वर्षों में इस देश ने बहुत ज्यादा देखा, वह परियोजना के क्रियान्वयन में ज्यादा समय लगना था। परियोजनाओं में जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों को लेने में जो प्रशासन होना चाहिए था, उस प्रशासन में अकुशलता थी। देश के सेवा क्षेत्रों का जिस प्रकार से विकास होना था, उन सेवा क्षेत्रों के विकास को हम पूरा नहीं कर पाए थे और देश में वस्तु उत्पादन क्षेत्रों का जो पुनरुद्धार होना था, उसमें भी कहीं न कहीं पॉलिसी पैरालिसिस था, इसलिए देशों में नए औद्योगिक पुनरुद्धार की आवश्यकता थी, इसको बहाल करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में प्रबंध किया है। इसलिए अगर इस बजट को देखा जाए, तो इस समय हमारे देश में चार महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं कि देश में इस संकट के समय से

निकलने के लिए हमें नए निवेश की जरूरत है। इस समय ऐसी आवश्यकता है कि जो देश की विकास गति है, उसमें आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जाए। कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से रोजगार कम हो रहे हैं, उसको देखते हुए गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए। देश में इस बात की भी आवश्यकता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है, उसको बढ़ाया जाए और कृषि की जो विकास दर है, उसको स्थायी रूप से बनाए रखना भी इस सरकार के सामने एक चुनौती है। मैं जब इस बजट का विश्लेषण करता हूं तो माननीय वित्त मंत्री जी बजट रखा है, अगर इसको तुलनात्मक आंकड़ों के द्वारा देखा जाए, जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि तथ्य किसी भी प्रकार से गलत सिद्ध नहीं करते, अगर आप इन आंकड़ो को देखेंगे तो निश्चित रूप से यह पता लगेगा कि जिन चारों विषयों की हमें आवश्यकता थी, निवेश की, आर्थिक स्थिरता की, गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने की, इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की और कृषि क्षेत्र की विकास दर को बनाए रखने की, उन सभी आवश्यकताओं को इस बजट में पूरा करने का प्रयास किया गया है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश का जो ऊर्जा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 2013-14 में जो बजट का वास्तविक खर्चा हुआ, वह 5,411 करोड़ हुआ। इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट के प्रावधान किए हैं, उनमें उसको बढ़ाकर 9,544 करोड़ किया और ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए इसे 76 प्रतिशत बढ़ाया गया। केवल यही नहीं, जो रिन्युअल एनर्जी है, जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि इस क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि क्यों नहीं हम इस देश में ऐसा प्रयोग कर सकते, जो बजट स्पीच में भी है, कि एक लाख किसानों के हैंडपंप तक हम सौर ऊर्जा का संचालन कर सकें। इसलिए पिछली बार, रिन्युअल एनर्जी में जो 438 करोड़ रुपए थे, उसको बढ़ाकर 956 करोड़ रुपए किया गया है और इसकी आवश्यकता को देखते हुए 118 प्रतिशत की वृद्धि उन्होंने बजट में की है। किसी भी क्षेत्र में अगर दस प्रतिशत या पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि होती है तो हम यह मान सकते हैं कि वह इन्फ्लेशन के कारण है, लेकिन अगर सरकार तीस प्रतिशत, चालीस प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि करती है तो यह सरकार की मंशा को दर्शाता है कि सरकार विकास की गति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहती है। इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह पीने के स्वच्छ पानी की है। आप सुदूरवर्ती भारत के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, पीने का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, फ्लोराइड का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। आम महिला, आम गांववासी इससे प्रभावित होता है। पिछली बार पीने के पानी के लिए जो 12,006 करोड़ रुपए थे, उसमें भी सरकार ने वृद्धि करके 15,267 करोड़ रुपये कर दिए और इस प्रकार उसमें भी 27 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं- ऊर्जा आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, रिन्युअल एनर्जी की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता ग्रामीण विकास की है। अभी स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने उस सदन में यह बयान भी दिया था कि इस देश में जो हमारे छोटे शहर हैं, आज अगर आप किसी भी जगह पर जाएंगे और छोटे शहरों को देखेंगे तो उन छोटे शहरों के पास छोटे-छोटे खेत काटकर हम नयी और अव्यवस्थित मानव-बस्तियों को बसाते जा रहे हैं। आज क्या इस देश में सौ से ज्यादा ऐसे शहर नहीं हैं, जिनके पास इस प्रकार की स्मार्ट सिटी को बनाया जाए, जिस स्मार्ट सिटी के माध्यम से उन छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को मूलभूत मानवीय सुविधाएं मिल सकें। आखिर क्यों हमारे कांग्रेस के मित्र इस बात को

[श्री भुपेन्द्र यादव]

स्वीकार नहीं करते कि जिसे संविधान में हमने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मनुष्य को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया था, उस सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार में आज भी हम स्वच्छ पानी, ऊर्जा और उनके रहने के लिए पर्याप्त मकान और सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। हिन्दुस्तान के सौ छोटे शहरों के साथ रूरल और अर्बन की बात करके माननीय वित्त मंत्री जी ने सौ छोटे शहर बनाए हैं और देश के गांव तक अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर को ले जाने की बात की है। यह इस बजट की दर्शन और नीति को दर्शाता है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, मैंने प्रारम्भ में भी कहा था कि अगर आपको देश की विकास दर को बनाए रखना है तो कृषि की जो विकास दर है, उस कृषि की विकास दर में सातत्यता, उस कृषि की विकास दर को सतत रूप से बनाए रखना बहुत आवश्यकता है। इस देश में बहुत सारे किसानों ने पिछले वर्षों में आत्महत्याएं की हैं। क्या कभी हमने आत्महत्याओं के कारणों का विश्लेषण किया है? इस देश में जो छोटा किसान है, जो बटाई पर जमीने लेता है, जो भूमिहीन किसान है, जो वास्तव में नकदी फसल में किसी किसान से उसकी जमीन उधार लेकर वहां पर खेती करता है क्या कभी किसी ने उसको गारंटी देने की कोशिश की है? क्या कभी किसी ने उसको ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश की है? हिन्दुस्तान के बजट में पहली बार हमारे वित्त मंत्री जी ने भूमिहीन किसानों को पांच लाख रुपए उनके समूह की गारंटी के आधार पर देने की बात कही है। इस देश के किसान की जो समस्या है, उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने एक प्रावधान किया है। उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी जो 2013-14 का बजट था, उसमें 26,071 करोड़ का प्रावधान था, इस बार उसमें 31,063 करोड़ रुपये बढ़ाकर, कृषि क्षेत्र में भी 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रयास किया गया है।

देश में मध्यम, लघु और जो सूक्ष्म उद्योग हैं और जो हमारा कुटीर उद्योग है, आज उसे आगे ले जाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कभी-कभी इस बात को कहा जाता है कि हिन्दुस्तान का जो मध्यम उद्यमी है, हिन्दुस्तान का जो लघु उद्यमी है, उसके लिए कोई स्थाई नीति बनाने की बात होनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के पैरा सं. 102 में कहा है कि वह जो क्षेत्र है, आज यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर आज हम नए रोजगार के क्षेत्रों को बढ़ाना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र से निकले लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो ये लघु उद्यमी हैं, मध्यम उद्यमी हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उद्यमी हैं, वे अधिकतर माइनॉरिटी वर्ग के हैं, शैड्यूल्ड कास्ट हैं, ये ओ.बी.सी. हैं। ये परम्परागत रूप से काम कर रहे हैं। यह सरकार इसलिए भी बधाई की पात्र है कि इसने तीन महीने के अंदर इनके लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया है और इस क्षेत्र में 25 प्रतिशत बजट आबंटन में भी वृद्धि की है।

इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश से जनादेश प्राप्त किया था, तो उन्होंने पूरे देश के सामने एक बात रखी थी कि हम हिन्दुस्तान को एक ऐसा हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं, जिसमें पूर्व और पश्चिम एक साथ तरक्की करेगा। यह सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहती है। आनन्द शर्मा जी सही कह रहे थे कि अगर इस बजट में देखा जाए, तो देश के हर प्रदेश के विकास की बात कही गई है, लेकिन

हिन्दुस्तान में पर्याप्त मानवीय संसाधन होते हुए, प्रकृति की अपूर्व सम्पदा होते हुए, देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है। हो सकता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार न हो, लेकिन जब हम समन्वित विकास की बात करते हैं, जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं, जब हम पूरे देश की बात करते हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में 2013-14 में पूर्वोत्तर के क्षेत्र के लिए प्रावधान 1830 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ाकर 2,333 करोड़ रुपए करके, उन्होंने 27 प्रतिशत की वृद्धि की है।

जब हम देश में सामाजिक विकास की बात करते हैं, जब हम इस देश में समावेशी विकास की बात करते हैं, तो हम केवल मार्जिनलाइज्ड एरिया की बात नहीं करते, हम केवल मार्जिनलाइज्ड कार्य की बात नहीं करते, बल्कि हम मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी की भी बात करते हैं। एक ऐसा समाज हो, जिसमें समाज के छोटे वर्ग को सबके बराबर लाकर काम करने की बात हो, सामाजिक न्याय को तीव्र गति से ले जाने की बात हो, एकीकृत करने की बात हो तो किसी भी बजट को देने में जो सबसे बड़ी बात देखी है, वह यह कि अनुसूचित जाति सब-प्लान में कितना पैसा दिया है। 2013-14 में जो पिछला बजट प्रस्तुत किया गया था, उसके अनुसूचित जाति सब-प्लान में 33,801 करोड़ रुपया दिया गया था, इस बार सरकार ने उसको 35 प्रतिशत बढ़ाकर 48,638 करोड़ रुपया किया है। यह सामाजिक समरसता का विषय है। मेरा यह मानना है कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और आन्ध्र प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति का वर्ग है, उसका विकास थोड़ा-थोड़ा और टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। समावेशी विकास की अवधारणा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में भी जानी चाहिए। पिछली बार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, ट्राइबल्स सब-प्लान में प्रावधान 22,030 करोड़ रुपए था, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 30,726 करोड़ रुपया किया है। देश में कभी यह कहा जाता है कि विकास में सभी समुदायों की समान भागीदारी होनी चाहिए। सभी समुदायों को विकास के काम में समान रूप से जोड़ना चाहिए। इसमें किसी भी जाति, धर्म, भाषा और प्रांत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। पिछली सरकार ने माइनॉरिटीज को बजट में 3,111 करोड़ रुपए दिए थे, इस बार 3,711 करोड़ रुपए देकर, इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि की है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी किया था, तो उसमें लिखा था कि इस देश में सात करोड़ लोग विकलांग हैं। हम जानते हैं कि जो सात करोड़ विकलांग लोग हैं, उनकी अनदेखी कभी नहीं की जा सकती। उन सात करोड़ लोगों के कल्याण और पुनर्वास की योजना बननी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बार, जब यह बजट बनाया गया तो उसकी एक विशिष्ट मद में विकलांग समुदाय के लिए अलग से 627 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट में समाज के हर वर्ग के उत्थान की बात मूल रूप से कही गई है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक बात कही थी। उन्होंने जब इवोल्यूशन ऑफ प्राविंशियल फाइनेंशियल ब्रिटिश इंडिया पर रिसच की थी, तब एक बात कही थी कि भारत का विकास कैसे होगा, भारत के प्रोविंशियल राज्यों को किस प्रकार से विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकास की भागीदारी और विकास का पैसा राज्यों के पास सीधे पहुंचाना चाहिए। जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश प्राप्त किया था, वह टीम इंडिया की बात थी। एक ऐसा भारत बनना चाहिए, जिसमें राज्यों को अपने संसाधनों, अपनी भौगोलिक और क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए

[श्री भुपेन्द्र यादव]

विकास के पूरे अवसर प्रदान करने चाहिए। पिछली बार के सेंट्रल प्लान में 3,56,000 करोड़ रुपये का जो केन्द्र का पैसा था, उस पैसे को इस बार कम किया गया है। पिछली बार सेंटर से राज्यों को जो, 1,19,049 करोड़ रुपये की असिस्टेंस दी गई थी, उसको बढ़ाकर 3,38,562 करोड़ रुपये किया गया है। यह कार्य संघवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा को मजबूत करता है। हम चाहते हैं कि देश के सभी राज्य प्रतिस्पर्धात्मक और सकारात्मक तरीके से अपने विकास को प्राप्त करें, इसलिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को विकास करने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। 184 प्रतिशत की राशि, जो सेंटर की स्टेट को असिस्टेंस है, यह राशि उस खाते में बढ़ाई गई है। यह जो संघवाद है, यह सभी राज्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार के बजट की नीति और दर्शन क्या है। इस सरकार ने स्वयं को एक फिंक्रमद और संवेदनशील सरकार के रूप में प्रस्तुत किया है। इस देश में कश्मीरी पंडित पिछले तीस सालों से जिस अन्याय के शिकार थे, इस सरकार ने उनके लिए 500 करोड़ रुपये देकर देश में विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों की सुनवाई की बात की है।

इस सरकार ने "बेटी बचाओं" जैसे कार्यक्रम को अपनाकर अच्छा कार्य किया है। आपको खुश होना चाहिए कि इस सरकार ने लड़कियों और महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए जिस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, हमें उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए।

आज देश में बहुत बड़े पैमाने पर संस्थागत और प्रशासनिक सुधार लाने की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और देश की आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है। क्या इस देश में यह आवश्यकता नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल जिस आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जो हजारों पुलिस वाले मारे जाते हैं, जो हमारा गौरव हैं, हम पुलिस स्मारक और युद्ध स्मारक बनाकर, नया प्रशासनिक तंत्र बनाकर उनको नैतिक साहस दें? वह साहस देने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश का विकास रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रतिभा और कुशल मानव संसाधन के द्वारा होना चाहिए। हमारे देश की जो पूंजी है, वह बहुत बड़ी संख्या में रक्षा उत्पादों को खरीदने में चली जाती है। क्या हम रक्षा क्षेत्र में अपना इन्डिजिनेस, हिन्दुस्तान का जो आयुध वगैरह हैं, उनको बनाकर अपने तकनीकी कौशल और मानव विकास के द्वारा देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं? माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में इसको करने का प्रयास किया है। इस बजट में उन्होंने केवल इतना ही प्रयास नहीं किया है, बल्कि उससे आगे बढ़कर मैं यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिस नीति और सिद्धांत को लेकर काम करती है, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय दर्शन है। हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन में विश्वास रखकर समाज के अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति की चेतना को जाग्रत करने, उसके जीवन को उठाकर

आगे बढ़ाने, उसको सामाजिक विषयों के साथ जोड़कर देश के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के दर्शन पर काम करना चाहती है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इस बजट में सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास और पुनरुद्धार पर भी ध्यान दिया गया है। हमारे देश भर में जो लाखों सफाई कर्मचारी बंधु रहते हैं, पिछली बार के बजट में उनके लिए 69 करोड़ रुपये का एस्टिमेटिड खर्च रखा गया था, लेकिन इस बार के बजट में उसको बढ़ाकर 437 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह हमारा अंत्योदय का दर्शन है। समाज के अंतिम स्थान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके लिए किस प्रकार के प्रावधान करके उसको समावेशी विकास से जोड़ना चाहिए, इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। मैंने कहा कि जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो उसमें मानवीय विकास और विरासत की बात भी आती है। यह विरासत दस सालों से आगे की भी है। इस विरासत का जो सांस्कृतिक संरक्षण है, उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने काफी प्रोविजन्स रखे हैं। मैं यहां पर उनसे दो और निवेदन भी करना चाहूंगा। पहला विषय मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं जिस शहर से आता हूं, उस अजमेर को विरासत की श्रेणी में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने उसके लिए विशेष रूप से प्रावधान किया है। अजमेर वह जगह है, जो पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी है, अजमेर वह जगह है, जहां ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का संदेश जाता है और अजमेर वह जगह भी है, जिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात माननीय आनन्द शर्मा जी कर रहे थे, वहीं ब्रह्मा जी का एकमात्र मन्दिर है। मेरा यह कहना है कि विरासत संरक्षण में अजमेर को जो पैसा दिया जा रहा है, वह उसे अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिया जाना चाहिए। अजमेर विकास प्राधिकरण में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी आती है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी आता है और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मन्दिर भी आता है। हम इस विरासत के माध्यम से अगर अजमेर विकास प्राधिकरण को इसका पूरा लाभ देंगे, तो हम देश में एक नए सांस्कृतिक जीवन मूल्य को, जिसको बढ़ाने की बात इस बजट में की गई है, उसे पूरा कर सकेंगे।

मैं एक और दूसरे विषय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के बारे में कहना चहूंगा। मैं कल डा. राममनोहर लोहिया के बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने एक जगह लिखा था कि तुलनात्मक दृष्टि से हिन्दुस्तान के तीर्थ केन्द्र बड़ी सांत्वना देते हैं। किसी भी महान मन्दिर के कोने में खड़ हो जाइए, एकाध घंटे में ही आप हिन्दुस्तान को चलते-फिरते देख सकते हैं। हम एक हैं, इतने एक हैं कि इससे हमें लगता है कि किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमें तोड़ कर दो बना सके। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में श्री जगन्नाथ जी का जो मन्दिर है, वहां पर हर 12-19 साल के बीच में कलेवर का परिवतन होता है। यह 1996 में हुआ था और अब यह विषय 2015 में आने वाला है। यह पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा महाकुंभ होता है। मुझे लगता है कि अगर केन्द्र सरकार उसके सांस्कृतिक विषयों को देखते हुए उस महाकुंभ के लिए भी कोई विशेष प्रावधान इस बजट में करेगी, तो निश्चित रूप से यह पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति के विकास के लिए अच्छा होगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट की फिलॉस्फी क्या है, यह बजट किस विषय पर आधारित है। मैरा यह कहना है कि the message of the Budget is: The Bugdet focuses on

[श्री भुपेन्द्र यादव]

development of marginalised sections of our society, marginalised regions of our country and marginalised sectors of our economy. It focuses on all basic development needs of our society. It also focuses on the equal opportunities to Indian citizens, Indian entrepreneurs and Indian banks to bring them at par with their global contemporaries. मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अभी तक विशेष रूप से जो दो सुविधाएं थीं, उनमें से एक एडवांस् रूलिंग की सुविधा थी, जो अभी तक हम केवल विदेशी फर्मों को ही दिया करते थे। एडवांस रूलिंग की सुविधाएं कभी भी भारतीय लोगों को नहीं थी, लेकिन इस बार पहली बार सरकार ने अपने बजट के माध्यम से यह प्रयास किया है कि एडवांस रूलिंग की जो सुविधा है, वह भारतीय व्यवसायियों और उद्यमियों को दी जाए।

दूसरी बात, इस बजट के द्वारा सरकार ने जो एक सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाने का प्रयास किया है, वह यह है कि बैंकिंग सुविधाओं का जो विस्तार है, वह 58 प्रतिशत है, सरकार ने उस 58 प्रतिशत को बढ़ा कर 100 प्रतिशत करने का प्रावधान किया है। लेकिन यहां पर मैं पुनः एक और निवेदन करना चहूंगा। हम ग्रामीण क्षेत्रों में नए बैंकिंग खाते शुरू करने की बात कर रहे हैं। जब आप इन ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों के लिए बैंकिंग खाते 100 प्रतिशत परिवारों को देंगे, तो उन ग्रामीण बैंकों के खातों के जो मुखिया है, वह आपको उस परिवार की महिला को बनाना चाहिए। अगर हम नीचे उस महिला को मुखिया बनाएंगे, तो महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी। मेरा उसमें यह भी कहना होगा कि उस बालिका या बच्चे के लिए ओ.बी.सी.. एस.सी., एस.टी. या माइनॉरिटी को जो स्टाइपेंड आता है, अगर वह उस मुखिया के एकाउंट में जमा होगा, तो निश्चित रूप से हम देश में एक नए आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत करेंगे। ये एकाउंट्स जीरो बैलेंस पर ऑपरेट होने चाहिए। इसलिए देश की सरकार ने सीधे-सीधे विकास कार्यों को, बैंकिंग कार्यों को बढ़ाने का जो काम किया है, मुझे लगता है कि यह बहुत स्वागत योग्य विषय है।

अभी यह कहा जा रहा था कि देर आए, दुरुस्त आए। मेरा यह कहना है कि देर आए, दुरुस्त आए, वह तो 66 साल बाद आ ही गए हैं, लेकिन किसी भी देश की जो तकदीर बदली जाती है, वह जहां चाह, वहां राह से बदली जाती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने एक संकल्प को अभिव्यक्त किया है। जिस जनादेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आई है, जिस जनादेश को लेकर हमने 'एक भारत - श्रेष्ठ भारत' के सपने को एक संकल्प के रूप में अभिव्यक्त किया है, मेरा यह मानना है कि देश में चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे हमारे व्यापारियों को एडवांस टैक्स रूलिंग में फायदा देने की बात हो, चाहे देश के कर ढांचे को सुधारने की बात हो, चाहे देश को वैश्विक स्तर पर खड़ा करने की बात हो, चाहे देश में गौरव संस्थान खड़े करने की बात हो, *...(समय की घंटी)...* चाहे देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, कुल मिला कर यह पूरे देश को सबका साथ और सबका विश्वास लेकर 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' बनाने के माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सपने को पूरा करेगा। मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री राजपाल सिंह सैनी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इस अवसर पर अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी कृपा से आज मैं राज्य सभा में बोल रहा हूं।

महोदय, आज भारत में अगर किसी वर्ग की दयनीय स्थिति है, तो वह किसान वर्ग है। ऐसा लगता है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किन्तु वह किसानों प्रति संवेदनशील नहीं रही है।

महोदय, जब आम बजट पेश किया जाता है, तो केवल दिखावे के लिए कृषि और किसानों का नाम लिया जाता है, जबकि देश की 70% से अधिक आबादी इसी पेशे पर निर्भर है। इस आम बजट में भी सरकार कृषि और किसान में मेहरबान दिखाई नहीं दी है। किसानों को उम्मीद थी कि ब्याजमुक्त ऋण से लेकर बीज, खाद, डीजल इत्यादि पर सीधी सब्सिडी किसानों को दी जाएगी, परन्तु ऐसा कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया है। किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर पानी फेर दिया गया है। अगर सरकार डीजल पर किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर पानी फेर दिया गया है। अगर सरकार डीजल पर किसानों के लिए सब्सिडी देती है, तो उस सब्सिडी का पूरा लाभ पूंजीपति और उद्योगपति उठा लेते हैं। इसलिए सरकार किसानों को डीजल पर सब्सिडी इस प्रकार दे कि उसका सीधा लाभ किसानों को मिल सके।

बजट में अगर किसानों को कुछ मिला है, तो वह है - 'कर्ज'। पहले ही किसान कंठ तक कर्ज में डूबा हुआ है। वह बैंक से ऋण ले तो लेता है, परन्तु समय पर उसकी अदायगी नहीं कर पाता, क्योंकि न तो उसकी फसल का भुगतान समय पर हो पाता है और न ही उसे फसल का लाभकारी मूल्य मिल पाता है। दैविक आपदाएं भी, चाहे ओलावृष्टि हो, बाढ़ हो या सूखा हो, उसकी फसल को नष्ट कर देती हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में ऐलान किया था कि किसान की फसल का लाभकारी मूल्य तय करते समय उसकी लागत से 50% अधिक मूल्य दिया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया।

महोदय, किसान को अपनी फसल तैयार करते समय जितनी लागत लगानी पड़ती है, उसकी तुलना में किसान को फसल का लागत मूल्य नहीं मिलता है। कृषि यंत्र और ट्रैक्टर आदि पर भी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। बजट में वेयरहाउस और सेंट्रल पूल मंडी की चर्चा की गई है, लेकिन इससे किसान को सीधा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान के पास एक-दो एकड़ जमीन ही बची है, ज्यादातर किसान सीमांत ही हैं। उसी जमीन से वह अपने परिवार का गुजारा करता है। उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह अपनी फसल का भंडारण कर सके, इसलिए वेयरहाउस और सेंट्रल पूल मंडी का लाभ भी बिचौलिए ही उठाएंगे।

महोदय, करीब 60%-70% प्रतिशत कृषि क्षेत्र अभी भी सिंचाई सुविधा से वंचित है। बजट में सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

[श्री राजपाल सिंह सैनी]

है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि सिंचाई के लिए दी गई 1000 करोड़ रुपये की राशि का लाभ किसान को किस रूप में मिल सकेगा। क्या किसानों को निजी नलकूप के लिए दी गई बिजली फ्री मिलेगी?

बजट में सिंचाई के सम्बन्ध में बुंदेलखण्ड की चर्चा कहीं भी नहीं है, जबकि सूखे के कारण बुंदेलखण्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, जब 80,000 करोड़ रुपये का पैकेज यू.पी.ए. की सरकार से मांगा गया था, जिससे बुंदेलखण्ड के किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। बहन कुमारी मायावती के बार-बार अनुरोध करने के बाद भी यू.पी.ए. की सरकार ने यह पैकेज नहीं दिया।

स्वदेशी पशुओं के लिए विकास के लिए भी बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस कार्य के लिए यह राशि काफी नहीं है।

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है, जबकि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए इस सरकार ने पहली बार गन्ना मिल मालिकों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। यह ऋण उनको इसलिए दिया गया है, कि ताकि वे गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर सकें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमे एक रुपया भी मिल-मालिकों को भुगतान के रूप में नहीं दिया है। यह किसानों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है?

महोदय, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तब बहनजी ने किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिया तथा समय पर किसानों का उसका भुगतान करवाया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान किसानों का एक पैसा भी मिल-मालिकों की ओर बकाया नहीं था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान किसान का एक पैसा भी मिल मालिकों की ओर बकाया नहीं था। यह निराशाजनक ही है कि किसानों की बुनियादी दशा में सुधार का सपना फिर अधूरा रह गया। एक ऐसे समय, जब सूखा एकदम सामने नजर आ रहा है और नेशनल क्राइम ब्यूरो की रपट यह बात सही है कि 2013 में लगभग 13 हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, तो उम्मीद की जा रही थी कि सरकार किसानों के लिए नई रोशनी लेकर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पिछले दस साल से देखा जा रहा है कि हर बजट में कृषि की बात होती है, लेकिन यहां-वहां एक-दो योजनाओं की घोषणा करके सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। बजट एक बार फिर से खेती की टिकाऊ और किसानों के लिए खुशहाली का सबब बनाने में असफल रहा है। सच तो यह है कि कृषि के नाम पर एक तरह के * का सिलसिला कायम है। बजट में किसानों को चार प्रतिशत की ब्याज दर आठ लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रख कर सुखद तस्वीर दिखाई गई है। लेकिन मान्यवर, सच्चाई यह है कि इसमें किसानों को केवल 60-70 हजार करोड़ रुपये की मिल पाएंगे, बाकी राशि एग्रो बिजनेस के लिए है। चार प्रतिशत ब्याज पर एग्रो इंडस्ट्रीज को कर्ज मिलेगा और उद्योगों का लाभ होगा, किसानों का नहीं। पहले आर्थिक सर्वेक्षण और उसके बाद आम बजट यह बता रहा है कि

*Expunged as ordered by the Chair.

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली समाप्त करना चाहती है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का फैसला इसी की एक कड़ी नजर आती है। इसका मतलब यह है कि अभी जो मंडियां हैं, उनके ऊपर ऐसी संस्था बनाई जा रही है, जो कुल मिलाकर निजी कम्पनियों के लिए द्वार खोलेगी, अर्थात् यह निजी कम्पनियों के लाभ का बजट है।

महोदय, आज तेल की कम्पनीज को तेल का भाव तय करने की आजादी है, उद्योगपति अपने द्वारा निर्मित सामान का भाव स्वयं तय करता है, दुकानदार अपने माल को अपने भाव पर बेचता है, परन्तु दुर्भाग्य है कि जब किसान की उपज का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है, तो किसान का कोई भी प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं किया जाता। उसकी फसल का मूल्य वे लोग तय करते हैं, जिनको यह भी पता नहीं होता है कि कितनी बार गन्ने, गेहूं, धान, सब्जी, दलहन, तिलहन को खाद व पानी दिया जाता है और कितनी बार किस-किस समय उसकी सिंचाई-निराई-गुड़ाई की जाती है। महोदय, मैं किसान का बेटा हूं, किसान हूं और स्वयं ट्रैक्टर चलाकर खेत तैयार करता हूं तथा उसकी बुआई करता हूं। मैं किसान के दर्द को भलीभांति समझता हूं। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि किसान की उपज का मूल्य तय करते समय उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

महोदय, कृषि और अनुसंधान के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। यह अच्छी बात है। नये कृषि अनुसंधान संसाधन खोलने की बात कही गई है। यह भी अच्छी बात है। इससे सरकार किसान का हित साधने की बात कर रही है। परन्तु महोदय, इससे आम किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वह पारम्परिक खेती करता है। उसको उन्नत बीज समय पर मिल ही नहीं पाते। किसान अपने लिए बीज स्वयं ही तैयार करता है। इन सब बातों को देखते हुए किसान की रुचि कृषि से हट रही है। इसलिए किसान की हालत में सुधार के लिए सोचा जाना चाहिए, जिससे वह खेती करना न छोड़ दे। अगर उसने खेती करनी छोड़ दी, तो इसका क्या परिणाम होगा, इससे सभी भलीभॉति परिचित हैं। आज खाद्य सुरक्षा बिल की बात जोर-शोर से हो रही है, लेकिन किसानों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। यदि इससे परेशान होकर किसान का कृषि से मोहभंग हो गया और उसने पैदावार करनी छोड़ दी, तो खाद्य सुरक्षा बिल का क्या होगा और खाद्यान्न की आपूर्ति कहां से होगी? आज कोई भी किसान अपने बेटे को कृषि के कार्य में नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि यह फायदे का कार्य नहीं है।

महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि किसानों की जो बहुत दिनों से एक आवश्यकता थी - किसान टी.वी., सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने किसान टी.वी. को इसी सत्र में, इसी मौजूदा वित्तीय सत्र में शुरू करने की बात कही है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इससे किसानों को समय-समय पर नयी तकनीकी का पता चलेगा और खेती का ज्ञान होगा। उसे जैविक खेती के बारे में पता चलेगा। इस बात के लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हमारे एक साथी भूमिहीन किसानों की बात कर रहे थे कि भूमिहीन किसानों के लिए कभी कोई प्रोविजन किसी बजट में नहीं किया गया। इस सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए पांच लाख रुपये का प्रोविजन किया है। लेकिन उसमें शर्त

[श्री राजपाल सिंह सैनी]

यह रखी गई कि संयुक्त कृषि समूहों को वे पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है, क्योंकि जब दो सगे भाई इकट्ठे खेती नहीं कर सकते, तो संयुक्त कृषि समूह कहां से खेती करेंगे? इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका लाभ उनको मिलेगा, बल्कि इसका लाभ भी पूंजीपति ही उठा पाएंगे, क्योंकि उनके पास वे समूह बने हुए हैं। किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।

महोदय, अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह बताना चाहता हूं कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आता हूं। मैं समझता हूं कि भारत में गन्ने की सबसे अधिक पैदावार मुजफ्फरनगर जनपद में होती है। मुजफ्फरनगर में एक समय एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी हुआ करती थी और वह आज समाप्ति के कगार पर है, जिससे इससे जुड़े किसान, कामगार और आढ़ती भारी नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए सरकार मंडियों के लिए ऐसी नीति बनाए कि मृतप्राय रोजगार में जान आ सके तथा इससे जुड़े किसान, कामगार और आढ़ती लाभ की स्थिति में आ सकें।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, according to astrologers, Saturn falls in the line of Mars and enters in the star sign Libra around the time the Budget 2014-15 was placed. Astrological forecast predicts a very tough time ahead in such combination of planetary situations. But I am not sure whether this astrological prediction has any effect on this Budget. शनि की जो अंतर्दशा है, वह इस बजट के ऊपर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, मुझे मालूम नहीं, वह तो आगे देखना पड़ेगा। But even before this Budget was placed, the Government hiked the prices of diesel, petrol, railway passenger fares and, particularly, the freight, resulting into abrupt rise in the prices of essential commodities, particularly, the vegetables throughout the country.

Sir, when I look at this Budget, I find it to be an extension of the previous Budget. Possibly, the Babus of North Block were waiting for change of guards, and only after 16th of May when the results of last Lok Sabha elections were announced, they started doing some denting and painting on the interim Budget placed in February, and this is how the interim Budget has turned to be an ad hoc Budget for the coming eight months.

Sir, everyone must agree with the hon. Finance Minister. Everyone must agree with the hon. Finance Minister that nothing can be achieved or done within forty-five days. It is true. Because of the sluggish economic situation, it is very difficult. Yet, everyone had expected that keeping in view the slogan, 'सबका साथ, सबका विकास'

there will be a new roadmap. But I am constrained to say that this Budget does not reflect any new vision or mission or a dimension for the hungry millions of our country. When I say so, I like to quickly refer to a few figures from the Millennium Development Goals Report, 2014 released by the Secretary-General of the United Nations very recently, wherein, it is stated that one-third of world's poorest of the poor people live in India alone who cannot earn even 1.25 dollar a day, that is to say, the people who cannot earn even ₹ 75 a day, and, incidentally, they constitute one-third of our total population. This is a situation that one-third of our population is poorest of the poor of the world. This Report also says that India is having the highest number of under-five deaths in the world with 1.4 million children are dying on an average per year before reaching their fifth birthday. Not only that, India has an estimated 50,000 maternal deaths per year which is the highest in the world. The Report further says that nearly 60 per cent of the Indians practise open defecation. Sir, this being an alarming situation, this Budget ought to have put special emphasis, considering these development indexes, on extending all support to all those who need it most. But, there is not even a ray of hope for one-third population of our country that figured in the UN Report. This Budget has not reflected any hopes or aspirations for that one-third population of our country.

Sir, this is the situation and I feel ashamed and shocked to know that while one-third of our population is not in a position to even maintain their animal existence, what to speak of living with human dignity, the Boston Consulting Group Report, 2014 says that India shall be the seventh wealthiest nation by 2018 in terms of the number of millionaires and billionaires. So, side by side, यह अंधेरा भी है, यह उजाला भी है। अंधेरा किसके लिए है और उजाला किसके लिए है, इस बारे में बजट में थोड़ी-बहुत चर्चा करनी जरूरी थी, लेकिन हमें अफसोस है कि इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई।

Sir, it establishes beyond doubt that the so-called economic reforms, being perpetuated since the early '90s, has immensely benefited the richest people of this country and not the poorest of the poor.

Sir, It is common knowledge that as the income gaps between the rich and the poor widen, a sub-nation emerged within the nation, leading to economic and social mutinies, which is writ large on every nook and corner of this country, and none of the governments has addressed this problem seriously.

Sir, from this Budget it is clear that the mandarins of the North Block have failed to look at the writings on the wall. Whenever there is a Budget, there is an in-built story of growth, and this Budget is no exception to that story of growth. There are beautiful

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

depictions about how it is visualized and how it is to be achieved. But, when I put the question to myself as to whether growth by itself can create an economically unified nation, pat comes the reply - no! Unless the entire character of development planning itself is changed, providing for more balance between rural and urban areas of the country as a whole, and treating it as an integral and economic hinterland, no inclusive growth can be achieved, particularly when the BPL census undertaken by the Ministry of Rural Development indicates and projects that half of India's rural population live below the Poverty Line. And yet, this Budget maintains the *status quo.*

Sir, the hon. Finance Minister has set a target of reducing the fiscal deficit from 4.1 per cent to 3 per cent in 2017. But the Budget lacks details on revenue and expenditure measures to lower the deficit. This Budget has attributed only one line, at page 3 of the Budget Speech, to the problem of black money, without mentioning anything about the action or sanction to be initiated against countries unwilling to disclose the Indian accounts, and also against the 498 Indian entities operating from different tax havens. The fate of ₹ 750 crores loan default scam involving the Life Insurance Corporation, to the benefit of a private company, is also not known. It reminds me of a similar Life Insurance Corporation scam in the early '50s, involving a Kolkata businessman, because of which the then Finance Minister, Shri T.T. Krishnamachari, had to resign. I want a clarification from the hon. Finance Minister. What is the fate of that ₹ 750 crore scam of the LIC? Sir, I have identified from this book 'Budget at a Glance', 25 schemes for which ₹ 100 crores have been allocated. There are fifteen other schemes and a paltry sum of ₹ 20 crores to ₹ 90 crores has been allocated. So, altogether, there are forty schemes in this Budget and the allocation for them ranges between ₹ 20 crores to ₹ 100 crores. I am just referring to a few of them like *Beti Bachao, Beti Padhao,* Madrasa modernization, tribal welfare and *ghat* development. I am not sure whether *ghats* include bathing ghats, ferry ghats and burning *ghats* too. But ghat development is a new thing that this Budget has highlighted. It is very good. But for these forty schemes, only ₹ 20 crores to ₹ 100 crores have been allocated. I would request someone from the Government to visit West Bengal and ascertain from our beloved leader Miss Mamata Banerjee, who is leading a Government in the most debt-ridden State of India, as to how she has allocated ₹1,000 crores for *Kanyashree* scheme which is identical to this *Beti Bachao, Beti Padhao* scheme, but initiated much earlier. This House will be happy to know that this Kanyashree scheme initiated by Miss Mamata Banerjee has got the appreciation of the United Nations and the United Nations has taken it up as a role model, and in the coming weeks in London there will be a summit to discuss on the pros and cons of this *Kanyashree* scheme and how to implement this scheme in other States of the world. Sir, this is the way a Government should function. But here we

have found that only a paltry sum of ₹100 crores has been allocated for *Beti Bachao, Beti Padhao.* Sir, similarly, ₹100 crores have been allocated for "Start Up Companies" for rural youth and I consider this is a cruel joke. This is a cruel joke to 55 crore youths of our country. Only ₹100 crores for "Start Up Companies" for the youth! Sir, if forty Central schemes which have an allocation of Rs.100 crore each is divided among 29 States and 7 Union Territories, what will be the actual amount to be received by the States and Union Territories? If it is equally divided, then each State or Union Territory will get only ₹ 2.77 crore for *Beti Bachao, Beti Padhao,* or Start Up Companies for youth, for Tribal Welfare, for Ghat Development and Madarsa Development. This is horrible, I must say. The Government must come out with a clarification on the matrix behind such laughable allocation. Sir, there are such other schemes too. I am quickly referring to two or three schemes. One, rupees hundred crore for soil health card for kisans. The Government is so sympathetic to kisans that only ₹ 100 crore has been allocated for soil health card for *kisans.* Only ₹ 50 crore are provided for blue revolution. What is that blue revolution? We have had white revolution and green revolution. What is that blue revolution? That is development of inland fisheries notwithstanding the prospect of export of prawns and other Indian fish to foreign markets. Then, Sir, ₹ 100 crore are provided for Madarsa modernization. How many Madarsas are there in the country? Thousands of Madarsas are there. What will be the share of each Madarsa if ₹ 100 crore is divided among 29 States and 7 Union Territories? And, they call this minority welfare! Next comes, ₹ 200 crore for national heritage cities. Which are the cities identified as national heritage cities? What is the criterion? Is it only for sites of pilgrimage or cities of rich cultural heritage with long historical background? This needs a proper clarification.

Sir, ₹ 100 crore have been allocated for *'Van Bandhu Kalyan Yojana. '*What a tribute to our brethren living in the forest zone of the country, the tribal people! Sir, for the Small and Medium Enterprises, nothing has been allocated but an assurance has been given that there will be a Committee to evaluate it, and, thereafter, appropriate steps will be taken. Whenever Government wants to bypass something, the Government constitutes a committee or a commission to put the issue into cold storage. How many committees are running there in this country? How many corporations are running there in this country? Commissions after commissions, and, committees after committees. Punchhi Commission was set up on the Centre-State relations. It submitted its recommendations in 2010. We are in the middle of 2014. Three and a half years have elapsed. The recommendations of Punchhi Commission are yet to be accepted by the Government. The previous Government did not initiate any action. I do not know whether the new Government will do anything. But because now there is a person like Shri Arun Jaitley at the helm of affairs, I sincerely believe that some action will be taken in this regard so that the recommendations of the Punchhi Commission are accepted.

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

Sir, the BJP's manifesto released on 7th of April categorically ruled out and disallowed the genetically modified foods without scientific evaluation. But what happened on 18th July, just five days back. It is reported that the Environment Ministry has given a green signal for field trials of GM rice, mustard, cotton, chickpea and brinjals. My question is: what change has taken place between 7th of April and 18tn of July? This House needs a clarification. Are you listening? What is your Swadeshi Jagran Manch saying in this regard? Kindly go through the *Organizer* paper; your paper, I believe. What has the Swadeshi Jagran Manch stated? They have made a hue and cry against this field trial of GM rice, etc.

Sir, ₹ 1,500 crore have been allocated for National Ganga Plan. When you say, 'national', you must keep in mind that Ganga does not emanate from Varanasi or ends at Varanasi. Ganga emanates at Gomukh in Uttarakhand, and, after flowing through vast tracks of Uttar Pradesh and Bihar, it merges with Bay of Bengal at Sagar Island in West Bengal. I would like to know whether the Government, while undertaking the National Ganga Plan, is aware of the fact that the Gangotri glacier near Gomukh, which is the source of Ganga, is receding at the rate of 19 metres per year, and, according to NASA, the total recession of the Gangotri glacier is 1,147 metre in the past 61 years. This is the estimation of NASA. Sir, global warming, of course, is one of the major reasons but rampant deforestation from Haridwar to Gangotri glacier, and, construction of a number of dams and bridges from upstream to downstream have created a situation that may lead to disappearance of Ganga, as the original flow of Saraswati river has disappeared. If the Government is serious about the National Ganga Plan, it should have more scientific and more ecological approach to the scheme than the emotional or religious passion being shown in some corners. Sir, the hon. Prime Minister, Shri Narendrabhai Modi, has time and again said that he has himself experienced poverty since his childhood. The commitment of poverty elimination was also reflected in the President's Speech delivered on June 9, 2014. But, in this Budget, only rupees one thousand crores have been enhanced in respect of MNREGA compared to last year's allocation, although MNREGA needs a much higher allocation to be a genuine guarantor of employment to the poor. When the country is confronted with severe drought, only one thousand crore rupees have been allocated for irrigation schemes. While the Centrally-sponsored schemes have been re-structured, the Union Government's assistance to the States has been drastically slashed from nearly ₹ 40,000 crores to under ₹ 6,000 crores. There is no mention about granting fiscal autonomy to the States and the demand of the States, including the BJP-ruled States, that there should be 50-50 sharing of Central tax revenue between Centre and States or, for that matter, inclusion of cess and surcharges for devolution to the States. Sir, there must

be a dispute redressal mechanism at the Central level to prevent the Finance Ministers of different States of India from visiting the corridors of North Block or the Planning Commission with begging bowls. And, I appeal to the Government to consider whether the Finance Commission can be given a permanent status by changing our Constitution. Sir, there is also no assurance of providing adequate compensation to the States for the revenue loss that will be incurred due to interest on GST, although rupees nine thousand crores were allocated in the last year's Budget. This Budget is also conspicuously silent about implementation of General Anti Avoidance Rule, popularly known as GAAR, which is being deferred from time to time to the benefit of the corporates. Sir, after this thing, the slogan of 'cooperative federalism', when I look at this Budget, I find the commitment made in the President's Address - and here I quote only one line from the Address of the President, "High priority will be accorded to bring Eastern region of the country at par with the Western region in terms of physical and social infrastructure." It is almost absent. Only one industrial corridor, that is, Amritsar to Kolkata industrial corridor, which was taken up by the previous Government, has been announced which will benefit not only the Eastern region but also some other States of Northern India also. That has been announced. If the Government is still interested in its 'Look East' policy, then I would suggest that the Amritsar-Kolkata industrial corridor must be extended up to Siliguri which is the gateway of Sikkim, Bhutan and seven North-Eastern States. Sir, no assurance has been given for granting adequate financial assistance to West Bengal in particular and Eastern States of Bihar, Odisha and Jharkhand despite the fact that the interest payments are increasing owing to debt stress of West Bengal inherited from the previous Government. I demand for a moratorium on all arrears and debts of West Bengal inherited from the past.

Sir, this apart, neither Horticulture University nor a textile cluster has been sanctioned for West Bengal in this Budget. So many horticulture universities and textile clusters in the country have been announced. In spite of the fact that West Bengal is the largest producer of fruits and vegetables in the country and has tremendous potential for raw silk and cotton, no textile cluster or horticulture university has been sanctioned.

It is a perennial problem with the jute industry. Among the seven jute-growing States of India, West Bengal has the largest number of jute growers apart from four lakh labourers engaged in sixty-two jute mills situated in West Bengal. Instead of patronising the jute industry in the same manner as the sugar industry has been given relief, the compulsory provision of jute packaging of foodgrains and sugar has been diluted substantially endangering the future of jute industry. Similar is the situation with the tea industry. In spite of the mandatory provisions in the Tea Act, 1952, the Tea Board,

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

which is a Central Government organisation, has neglected and failed to come to the rescue of the tea plantation workers and extend assistance in improving their sub-human conditions.

A mere slogan of cooperative federalism will not do. When you talk about partnership and participatory democracy, the Government must recognise that India has no otner identity than 'a Union of States' as enshrined in the very first Article of the Constitution of India. And this Article of the Constitution of India is an article of faith to all the Indians living in this country.

Sir, India is a federation. The Government must also recognise that the States are closer to the ground and, therefore, more effective in delivering public services like food, health, education, roads, transport, etc. Even the fields like agriculture, industry, irrigation, power generation and supply, etc., are the core areas where the State-sponsored schemes and policies depending upon diverse socio-economic and geological considerations run successfully than the Centrally-sponsored schemes. The Government must adhere to the recommendations of the Sarkaria Commission and the Punchhi Commission on the Centre-State Relations in this regard. Once it is done, the States would receive an appropriate increase in their shares of the divisive pool to be recommended by the Fourteenth finance Commission.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

I would urge upon the hon. Finance Minister to look into this aspect with all seriousness. This would also end the Planning Commission's role as a fiscal agent for devolution of resources at its whims and fancies.

Sir, there is a popular belief that after being routed in the last Lok Sabha election in West Bengal, the BJP led Central Government has resorted to political vendetta against the State. I am sorry to say this.

Sir, I do not know whether this Budget is a *sanjivini or vishalya karani*, but to the "people of West Bengal, this Budget is a jar full of hemlock and as it is said in sanskrit "मधुतिष्ठति जिह्वाग्रे ह्रदयेतु हालाहलं।" बहुत सारी बातें यहां कही गईं, लेकिन अगर हम अपने राज्य की तरफ देखेंगे, तो फिर यह हलाहल है, जहर है।

Of course, my party does not hold this two-month old Government responsible for all evils of 67 years of Indian independence. No. It cannot be. No one can hold this two-month old Government for all these evils. But this Budget, as it appears, is essentially a Budget for corporate honchos, crony capitalists, FDI, Fll and PPPs. It is not meant for ensuring economic justice and equality to the larger section of Indian society.

Sir, millions of our countrymen sincerely hoped and believed that there would be *parivartan* or a sea change by their introducing well orchestrated slogan of 'Minimum Government and Maximum Governance."

Now, it appears FDI, FDI, FDI everywhere. FDI in Civil Aviation, FDI in Railways, FDI in Real Estate, FDI in Defence, FDI in Agriculture, FDI in banking and FDI in insurance. हमारा जल, थल, अंतरिक्ष एफ.डी.आई. के कब्जे में चला गया? क्या हम देश और जनता को भी एफ.डी.आई. के पास गिरवी रख देंगे, यह सवाल आज पैदा हो गया है। क्या आज सरकार चलाने के लिए भी हमें एफ.डी.आई. की मदद लेनी पड़ेगी? यह सवाल पैदा होता है कि इस देश में आज हो क्या रहा है?

Sir, I know that the hon. Finance Minister's hands are tied in the given situation to present this Budget. But he has assured that the steps highlighted in the Budget are only the beginning. If it is a beginning, I do not know whether it is the beginning of the end or not. But it is said, "Morning shows the day" but not necessarily the manner in which the Budget has shown no way out.

Sir, I would like to conclude here with a few words from Great Indian Poet Gurudev Rabindranath Tagore, although I have three minutes to conclude:

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে নীচে
পশ্চাতে রেখেছো যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে
হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

I can't translate the Bengali couplets of Gurudev but I will make an attempt "Those you trample under foot, drag you down; Further backward they recede, the less you advance; Your brethren you have treated with disrespect; You must share with them all, their ignominy." This is what Rabindranath Tagore said 100 years ago against the social, political and economic exploitation of the British rulers. I am appealing to the new rulers of this country to adhere to the caution given by Poet Gurudev Rabindranath Tagore. With these words, I conclude. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Shri Pavan Kumar Varma. It is his maiden speech. So, please take 15-20 minutes maximum. Try to complete in 15 minutes.

SHRI PAVAN KUMAR VARMA (Bihar): Thank you, Sir. I rise to make my maiden speech in this august House. I would like to thank you for the time you have allotted to me. I would also like to thank my party; and my leaders for this opportunity.

Let me begin by congratulating the hon. Finance Minister for his maiden Budget speech. If I may share with the house, I have known him from childhood. We were in school together. We were in St. Xavier School, Delhi together as class fellows. We were contemporaries in the University. Even then we debated against each other; and

[Shri Pawan Kumar Varma]

we went to the Law Faculty together. Let me say, Sir, that this personal association should not be held against him, but it is a privilege for me.

Let me also begin, Sir, by making a confession before this House. At the time of the elections, when the BJP came out with the slogan, 'सबका साथ-सबका विकास', I must say, with honesty, that I was deeply impressed. It indicated to me a holistic vision about the country which would encompass, with that vision, the benefit and the progress of the country as a whole. So, the hon. Finance Minister had said that we need not have a partisan debate, and I want to endorse that. I am not here to doubt his intention. But I must say that as I read the Budget speech, although with great humility I want to say that I am not an Economist, as I analysed it, my admiration for that slogan, 'सबका साथ-सबका विकास', came increasingly under greater scrutiny. Sir, I am not doubtingtheintention,buttherehastobeaco-relationbetweenintentionandsubstance. The great poet, Mirza Ghalib, said,

"रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल।
जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या।।"

Sir, intentions must show in terms of substance. A week after the Budget was presented, which my colleague, Shri Sukhendu Roy, also referred to, and I share this with this House not in a partisan mood, there was the Report of the U.N. Millenium Development Goals Project, 2014, and as was also stated earlier, it was a damning indictment of our nation, which said that one-third of the absolutely poor on this planet live in our country. And the Report also acknowledges that the rate of reduction of this poverty has been sluggish. Sir, these are statistics. ये आंकड़े जब हमारे जेहन में उतरते नहीं हैं, हमें चुभते नहीं हैं। पर यह खौफनाक हकीकत है, हमारे सामने। एक दर्दनाक हकीकत है, एक दुखदायी हकीकत है और जब 'सबका साथ-सबका विकास' की बात होती है, then, we must see in what manner this Budget tackles the needs of those who are less assertive, who are less eloquent, who are less seen and less heard, but who live in grovelling, demeaning, unacceptable and absolute poverty. And I want to give some examples. Sir, I seek this as a clarification as well. I do not want this to be acrimonious. I want to ask of the hon. Minister about some examples that I want to put before this House. Agriculture has been referred to. Fifty per cent of our workforce is associated with agriculture and the maximum number of poor are today associated as a part of the agricultural sector. Our food productivity is very low. China's rice yield per hectare is twice that of India. Even Indonesia's and Vietnam's are fifty per cent more in terms of their yield per hectare. Even Punjab, which is a developed agricultural State, has a yield of 3.8 million tonnes per hectare when the international average is 4.3 tonnes. Quite obviously, Sir, if our attempt is to reach those people who are at the very lowest end of the socio-economic spectrum, agriculture needs a massive boost in productivity, a new

investment, a new vision, a new road map for this sector which continues to grow at, what is derisively called, the Hindu rate of growth, and even today is targeted at as low as four per cent. To be honest, the Finance Minister does not disagree. In his speech, he says, and I quote: "We agree that a major portion of our population is dependent on agriculture for livelihood." He speaks about a technology-driven second Green Revolution. He emphasizes the need to step up investment, both public and private, and in Rashtrapati's speech, he lays down the broad framework and goals of this Government. He has said that he wants to convert farming into a profitable venture through scientific practices and agro technologies. The rhetoric the intent is there, Sir. But what has actually been given? Sir, it has also been mentioned that Rs. 100 crores for research work be given, for two more institutes on the model of Pusa. Sir, our Prime Minister has just returned from Brazil. It was obviously a very successful meeting. Brazil spends 1.7 per cent of its GDP on research and agriculture. Sir, Rs. 200 crores for four agricultural universities, Rs. 100 crores for a nation wide Soil Health Card Mission with Scheme, Rs. 100 crores for National Adaptation Fund to meet the challenge of climate change, and as Mr. Roy said, Sir, Rs. 50 crores for cattle breeding nation-wide and for the kind of relationship between agriculture and cattle breeding and livestock, Sir, the total of this is listed as highlights of the Budget. It is Rs. 550 crores. I am not doubting the validity of other sectors; National Highways, Sir, for instance, is important at its own level. It has been given Rs. 37,880 crores; Ports-Rs. 11635 crores. Agriculture, Sir, through the highlighted schemes, is Rs. 550 crores. It is true that amounts have been allocated for agricultural credit to be advanced. Sir, I ask this as a question. This is a continuation of old policies. But in fact, in terms of agricultural credit the allocation has been reduced. In 2013-14, the total credit allocation for agriculture and allied activities was Rs. 10,036 crores. In this Budget it is Rs. 10,026 crores. Now as for agricultural credit, advanced by Scheduled Commercial Banks, I would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister that the disbursement is completely skewed. Eastern India comprising Bihar, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands get 8.8 per cent of what is disbursed through the Commercial banks. The Northern Region gets 20 per cent, the Western Region gets 15 per cent, Southern India gets 38.5 per cent and 8.8 per cent is what Eastern India gets. And Bihar with a population, which is almost ten per cent that of India, gets only 2.3 per cent! Sir, the third problem in this is that even if you increase the allocation in terms of credit to the farmer, you must recognise that most farmers live at subsistence level. They cannot avail of these loans. Sometimes they do not even have the adequate title in order to be able to be entitled for that loan. Sir in my party's manifesto, and I will be very happy to share it, there were at least ten points made on what you could do in order

[Shri Pawan Kumar Varma]

to ensure that that credit can be made available to the needy and the poor and the marginal farmer. How can we make that available? I would urge upon the Finance Minister to have a look at that in order to see how credit can actually reach the farmers.

Sir, coming to irrigation, this is a House which is directly linked in many ways to the grassroots reality of India. Irrigation and agriculture are so linked, Sir, and we know the truth. Sixty-four per cent of our land is dependent on the vagaries of the monsoon. We also know, that this year we are likely to go through what could be a partial drought. The necessity of allocation in this sector on a far more magnanimous and dynamic scale was self-evident. We also know that only about 30 per cent of the net cultivated area, have benefited from irrigation projects that have been implemented so far. Again, Sir, the intention is clear. Rashtrapatiji in his अभिभाषण said, Sir, "My Government is committed to giving high priority to water security. It will complete long-pending irrigation projects on priority and launched the *Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana* with the motto of 'हर खेत को पानी'। In the Budget, the hon. Finance Minister said, 'bulk of our farm land is rain-fed and dependent on monsoon. Therefore, there is a need to provide assured irrigation to mitigate risks.' Sir, aware of the situation and having made their intent clear, I am perplexed that under their flagship scheme which is the *Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana,* an allocation of just ₹ 1,000 crores has been made! I question this only in terms of priorities of the Budget. Which India are we addressing ourselves to? This is the question to which policy-makers have to find answers.

In the JD (U)'s Manifesto, and I don't want this to be about one party versus the other, we have spoken about the urgent need to create a National Irrigation Authority. But, obviously, the kind of emphasis and detailing that needs to go into priorities is missing. Sir, I would like to mention some other vulnerable sectors such as women. Hon. Finance Minister has allocated ₹ 150 crores for increasing safety of women in all major cities. Sir, ₹100 crores for *Beti Bacho, Beti Padhao Yojana.* There are innovative schemes. We are looking at the future of this country. Once again, I make a reference to Bihar, because there has been a veritable revolution there in terms of education of the girl child. The landscape has changed. You can see girls on cycles, dressed in uniforms and going to schools across any part of Bihar through innovative schemes and investments. But, you have given just ₹ 100 crores ! What are our priorities?

I don't want to make this again uselessly acrimonious. But, ₹100 crores for modernisation of Madarsas -- ₹ 15 for per Madarsa! What does this allocation mean? And, again, it has been mentioned that ₹200 crores for a statue for a man whom we all greatly respect. But, knowing the man, if he knew that such small amounts are given for

other major priorities, he may have been rather embarrassed by a statue for himself of that cost. This is the question before us.

Sir, I have a question for the hon. Finance Minister on education and health, because it touches the lives again of the deprived and vulnerable. It is a major priority for this nation. I am unable to understand that revenue budget - I am not an economist, so I am willing to be corrected - has been slashed from an outlay of ₹ 67,301 crores for education, sports, art and culture in 2013-14 to ₹ 31,641 crores in 2014-15. This represents a reduction of 53 per cent! But, the outlay on education has gone up by 11 per cent in terms of capital expenditure. So, I would like to ask the hon. Finance Minister that if revenue budget has been slashed to such an extent and fixed costs have to be meant for salaries, pension, maintenance and equipment, how this outlay is going to be achieved. Let me say that one of the problems facing us is the quality of education in our schools. We have to raise the quality of teachers who are so trained. But Sir, only ₹ 30 crores has been allocated for School Assessment Programme!

Similarly, health is an exceptionally important matter. There are more malnutritioned children living in India than in Sub-Saharan Africa. More people die of simple diseases like dysentery and malaria in India than anywhere else. To my mind, again, there is a huge reduction in the revenue budget shown. ₹ 15,645 crores in 2013-14 to ₹ 11,114 crores in 2014-15 representing a slash of 29 per cent! And, as a percentage of the Budget - this is really something which I hope we can provide a clarification for - in a country like ours where this sector has so much importance, the allocation for health has come down from an already unbelievable low of 1 per cent of the Budget to 0.7 per cent of the Budget. Sir, it is an Important matter. I say this because the Planning Commission has said that the Government-run healthcare system is short of doctors by 76 per cent. We have less than half the number of nurses we need. The laboratory technicians are short by 80 per cent! Sir, the hon. Finance Minister has proposed setting up of AIIMS-like institutions in several States. He has provided a token sum of ₹ 500 crores for this. But, I would like to submit to him with a great humility that this is a drop in the ocean. The country needs 12 lakh doctors and 36 lakh nurses in order to meet the WHO norms. Sir, we have only 5.5 lakh doctors and 4 lakh nurses. I would like to draw the attention of this House that in 2011, China admitted 8 lakh students to medical institutions. Our figure was an abysmal 42,000. Sir, this sector needs attention. There are other things about China to emulate apart from their Bullet Train.

Sir, about equitable balanced regional development, as I speak in the Council of States, I also speak for the interests of Bihar. ...*(Time-bell)*... Sir, it is my maiden speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken 17 minutes, you can take three more minutes, that is all.

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: Sir, I want to say that in this Budget, there has been an institutional neglect of the least developed States and the neglect of Bihar which has voted so strongly in favour of the BJP in the last Parliamentary elections. It almost amounts to a betrayal of the trust of the people. Sir, where is Bihar in the scheme of industrial corridors and smart cities? Where is Bihar in the scheme of SEZs? Where is Bihar in the special schemes needed to reduce poverty because Bihar has had the highest GSDP rates in the country and has also achieved in the most terms of the highest number of people redeemed from below the poverty-line? Sir, there are no schemes. We had asked for an affirmative action for the least developed States. The BJP was a party to the call for Special Category Status to Bihar. You were there fighting with us at your own level. There is no mention about this affirmative action. Sir, this is a great lacuna in the Budget.

I want to end by saying that, perhaps, the approach of the Finance Minister was that let there be growth irrespective of its inclusive content. But, I want to say, Sir, even on that, there are grave doubts in terms of many of the schemes including, above all, their sustainability of a GDP deficit of 4.1 per cent and the concessions that are but marginally given to the middle-class etc.

Sir, I crave your indulgence for a minute more. In conclusion, I think, the real problem of this Budget is that it falls flat between many stools because it lacks a central roadmap and a vision- न खुद ही मिला न विसाले सनम। The intent was good, Sir. There is a couplet of Faiz. These days we have a very good relationship with Pakistan. So to quote Faiz:

‘दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम,
कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई।’

Sir, the slogan was ‘सबका साथ-सबका विकास’,; I am sorry, I don’t want to wish to sound acrimonious. But, at some times, it appears, ‘सबका वोट-कुछ विकास’,। सर, अच्छे दिन आने वाले नहीं है, अपने दिन आने वाले हैं। Therefore, we have to think. I will end with just four lines from a great leader. Please allow me because this great leader wrote in a book, which I had the great privilege to translate, on his request, his poems from Hindi into English. His name is Atal Bihari Vajpayee. The BJP now, Sir, is at a pinnacle. They have an absolute majority. They look at the stars but their feet are to be on the ground, and this is what Mr. Atal Bihari Vajpayee said, Sir:

'सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती,
सबसे अलग-थलग, परिवेश से पृथक,
अपनों से कटा-बंटा, शून्य में अकेले खड़ा होना,
पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है।
ऊंचाई और गहराई में आकाश-पाताल की दूरी है।।'

Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Muthukaruppan. Mr. Muthukaruppan, is it a maiden speech for you?

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): Yes, Sir.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, this is the session of maiden speeches.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, you take 15 minutes.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Very well, Sir.

Mr. Deputy Chairman, Sir, this is my maiden speech. I am nominated and elected as Member of this House from the AIADMK Party. My party Supremo and its General Secretary, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, is a revolutionary leader. This greatest opportunity is given to me by Hon. Amma. I am one among 250 Members of this august House. So, first of all, my sincere thanks to hon. Puratchi Thalaivi Amma, the Chief Minister of Tamil Nadu.

Sir, as far as the Union Budget 2014-15 is concerned, my leader welcomed it. I also welcome it. Sir, I would like to say that many of the announcements made in the President's Address have been given concrete shape in the Budget.

Further, Sir, the setting up of the Expenditure Management Commission is a welcome development, and I do hope that the Commission will address the issue of expenditure management in the appropriate socio-economic context of the country by keeping the welfare objective in view. I expect that there will be opportunities to voice our concerns regarding ensuring food and fuel security to the poor and weaker sections before the Commission.

Sir, hon. Amma also welcomed the assurance of the hon. Finance Minister that he will be more than fair to the States in addressing their concerns regarding implementation of GST relating to both fiscal autonomy and compensation of revenue loss issues.

Sir, the proposals relating to permitting FDI need to be approached with caution, in particular, the proposal to permit manufacturing entities set up with FDI to sell their

[Shri S. Muthukaruppan]

products through retail, including e-commerce platforms should not extend to permitting FDI in retail. Sir, again, I mention that you should not extend it to permitting FDI in retail.

Sir, I welcome the programme to establish 100 smart cities, in which, Ponneri is included as a smart city in Tamil Nadu, and for that I thank the Government of India.

Sir, I welcome the National Industrial Corridors, including Chennai-Bangalore Industrial Corridor and Vizag - Chennai Industrial Corridor, linking Chennai and thereby helping neighbouring States to take advantage of its natural strength. Sir, here, I would like to state that it does not benefit many backward regions and districts in Tamil Nadu. Sir, my request to the Government of India is that it must consider further extension of these corridors within Tamil Nadu.

Sir, Madurai-Thoothukudi Industrial Corridor proposed to be implemented by Tamil Nadu can be considered as part of the East Coast Corridor by extending it to Vizag-Chennai Industrial Corridor further South.

Sir, I also welcome the Scheme to set up a Textile Mega Cluster in Tamil Nadu. I further welcome implementing the programme for differently-abled. At least, one Braille Press will be established in Tamil Nadu.

Sir, I also welcome the announcement of establishment of the National Institute of Ageing at Madras Medical College.

Sir, the Government of Tamil Nadu has received a letter from the Union Minister of Health, Government of India, to identify three or four suitable alternate locations for setting up of a new AIIMS hospital in the State. Sir, I also request the Government of India to kindly include Tamil Nadu in the first place for setting up an AIIMS institution during the current financial year itself. For this purpose, Sir, as required by the Government of India, Amma's Tamil Nadu Government has already identified the required extent of land at Chengalpat in Kancheepuram District, Pudukottai town in Pudukottai District, Sengipatti in Thanjavur District, Perundurai in Erode District and Thoppur in Madurai District where lands with suitable connectivity are already in the possession of the State Government and its agencies.

Further, Sir, I request the Government that Tamil Nadu is included in the list of States in which AIIMS institutions would be set up during the current financial year. I want to stress once again, Sir, the AIIMS institutions should be set up during the current financial year.

Further, Sir, Tamil Nadu Government has 19 medical colleges. The additional seats have been sanctioned, but have not yet got formal approval of the Medical Council of India. For the academic year, 2014-15 the Government of India is requested to impress upon the Medical Council of India to expedite the approval and permit admissions to the medical students.

Further, Sir, we welcome the steps to boost tourism including proposals of heritage towns, including Kancheepuram and Velankanni. I would appreciate if Srirangam is included.

I invite attention to the need to enhance the allocation for the modernization of police force scheme. There is a need to support the setting up of a marine police station in Tamil Nadu.

Another important point is regarding linkage. I urge the Government of India to have a detailed study completed at the earliest, stage. As far as my district Tirunelveli is concerned, the Tamiraparani River originates from the peak of the Pothigai Hills and eastern slops of Western Ghats. The major tributaries of Tamirabarani River are Karaiya, Manimuthar River, Gadananathi River, Pachaiyar River and Chittar River. The river flows in two districts of Tirunelveli and Tuticorin. The Tamirabarani River provides a large proportion of the water for irrigation and power generation for Tirunelveli District. It is fed by both the monsoons, the south west and the north eastern. The river is the lifeline of the people of Tirunelveli District. It is a perennial water river having copper tinge. I request the Minister of Finance, the hon. Leader of this august House, to include this holy river in the Ganga rejuvenation programme for cleaning Tamirabarani River.

Further, Sir, I come to the shortfalls in release of grants. The Government of India sanctioned and approved Central schemes which were executed by the State of Tamil Nadu. The grants-in-aid are pending for release of money. There are major grants in aid due from the Government of India up to 2013-2014. This has adversely affected the fiscal health of the State. The Thirteenth Finance Commission recommended a general performance grant of Rs.1888 crores to local bodies in Tamil Nadu for the period 2011-12 to 2014-15. As against this amount so far only ₹125 crores have been released up to 2013-14. The rest of the amount may be released as early as possible. Further, Sir, five flood protection works in Tamil Nadu were accorded clearance by the Union Planning Commission in 2009-10 and 2010-11 for an amount of ₹ 613.43 crores with a Central share of 75 per cent amounting to ₹ 460.07 crores. All five works have been completed in 2012-13 and a total amount of ₹ 625.77 crore has been spent but the Government of India released a grant of only ₹ 59.82 crores. So, the hon. Finance Minister of India and hon.

[Shri S. Muthukaruppan]

Minister of Water Resources should release the recommended grant of Rs.388.8 crores to Tamil Nadu. Now I come to the grant for *Sarva Shiksha Abhiyan.* The Ministry of Human Resource Development had, in 2013-14, sanctioned ₹ 4.38.38 crores towards committed liability of teachers' salary component. Out of this, 65 per cent Central share works out to ₹ 284.95 crores. And, against this, the Government of India has released only ₹ 57 crores. The balance of ₹ 228 crores is still awaited.

Under the Right to Education Compensation Scheme, the reimbursed amount of Rs. 25.13 crores is pending. I would like to request the Government of India to release this amount.

Now, I come to the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Scheme. For the year 2011-12, the revised Project Approval Board approval is ₹675.05 crores. The Central Government's share is ₹ 506.09 crores, which has not yet been released. It has to be released.

In addition, there are grants from the Thirteenth Finance Commission for roads, maintenance of bridges, slum improvement, coastal protection, renewable energy, and also grants for post-matric scholarships for the Scheduled Caste students, statistical strengthening project, Comprehensive Handloom Development Programme, revamped Central road fund and the family welfare programmes. Here, the total amount of pending grant is ₹ 1,576.8 crores. It may kindly be released at the earliest.

Further, the Government of Tamil Nadu has implemented so many schemes, such as, free-of-cost 20 Kg. rice is given to all ration card holders, every month; mixies, grinders and fans are distributed free of cost to all ration card holders in order to ensure the welfare of women; milk cows and goats are distributed free of cost to the downtrodden people; fourteen items are given free of cost to the school-going students, which includes laptop, bicycle, text-books, note books, geometry boxes, uniforms, etc.; under the Amma Unavagam implementation, comes low-cost restaurants and Amma Mineral Water. For the implementation of so many welfare schemes, development schemes and infrastructure promotion, the Government of Tamil Nadu needs more money. I request the hon. Prime Minister of India and also the hon. Finance Minister to sanction more money to the State of Tamil Nadu.

Then, 1 come to another essential thing. The actual requirement of kerosene oil, as per the entitlement of ration card holders, in Tamil Nadu is 65,140 kilolitres per month. But, against this entitlement, the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, had allotted 59,780 kilolitres, per moth, up to March, 2010. Thereafter, this

allocation was successively reduced on ten occasions, in the last few years. Now, the monthly allocation of kerosene for Tamil Nadu is just 29,056 kilolitre, which is only 45 per cent of the State's requirement. While we were hopeful that the trend of arbitrary and unjust reductions in kerosene allocation would be reversed and some of the cuts imposed by the pervious UPA Government would be restored, it was disappointing to learn that even in the latest order, dated 1st July, 2014, Tamil Nadu Government has been allocated only 29,060 kilolitre of kerosene per month, which was the same as was allocated for the preceding quarter. Therefore, I request the Government of India to urgently allot the entire requirement of 65,140 kilolitre kerosene, per month. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, wind up, please. *...(Interruptions)...*

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): It is his maiden speech. Sir. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Maiden speech means 15 minutes only. *...(Interruptions)...*

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Further, Sir, I want to make two, three points. I will finish in two, three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, when my Leader, the Chief Minister of Tamil Nadu and the General Secretary of AIADMK Party, Puratchi Thalaivi Amma, was a Member of this House, in the year 1985, on March 14, she delivered a speech. With your permission, Sir, I would like to read out that speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Full speech ! No, please. You can quote.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, very briefly, I will mention.

DR. V. MAITREYAN: Sir, he is only quoting.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can take maximum of two or three minutes, not more than that.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, my Leader delivered a speech. She represented for a particular cause which has not yet been completed. Still, it is going on. Sir, my Leader said, "l am not arguing with the Indian Foreign Policy of non-interference as the internal affairs of another country, but where it involves the fishermen of our country, what is the use of our military might?" She raised this point in 1985. "How do we justify the enormous expenditure every year on Defence? If we do not utilise that military might

[Shri S. Muthukaruppan]

to provide protection to our own citizens, the fishermen of Rameswaram, how can the Government of India afford to allow any country, big or small, to get an impression that it can intrude with impunity into our territorial waters, attack and kill our citizens?" Sir, my Leader, Puratchi Thalaivi Amma raised this fishermen problem in the year 1985, March 14. So far, this matter has not been settled. Permanent solution is retrieval of Katchatheevu island.

Then, Sir, as far as Katchatheevu is concerned, it is a small island, spread over 2.85 acres, in the Palk Strait of Rameswaram, Tamil Nadu, which is part of Rameswaram district. It was originally under the ownership of Raja of Ramanathapuram. The Indian fishermen enjoyed traditional fishing rights in and around the Katchatheevu Island and Palk Bay. The two agreements were made in the year 1974 and 1976. Then, Mrs. Gandhi was our Prime Minister. Then, * ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You cannot criticize. ...*(Interruptions)*... That is expunged. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): The State Government has nothing to do with that. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is expunged. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): There was a resolution.. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. ...*(Interruptions)*... Muthukaruppanji, ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, this is his maiden speech. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will deal with it. ...*(Interruptions)*... You allow me. ...*(Interruptions)*... Mr. Tiruchi Siva, sit down. ...*(Interruptions)*... I will deal with this. ...*(Interruptions)*... Mr. Muthukaruppan, you cannot criticize a person who cannot come here and defend himself. Therefore, I am expunging that portion. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: It is a wrong representation of ...*(Interruptions)*...

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: What I said was, two agreements were made in the years 1974 and 1976. At that time, Mrs. Gandhi was the Prime Minister of India. *(Time-bell)*... Then, * ...*(Interruptions)*

*Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Both are expunged. ...*(Interruptions)*... Both references are expunged. ...*(Interruptions)*... Sit down. I have expunged them. ...*(Interruptions)*... I have expunged them. Now, you have taken 18 minutes. ...*(Time-bell)*... Your time is over. ...*(Time-bell)*...

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, please give me two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. It is already 18 minutes. ...*(Interruptions)*... I gave you two minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: My Leader ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Don't come to controversies unnecessarily. ...*(Interruptions)*... I gave you two minute's time.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, I need one minute to finish it. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: We want to settle that controversy. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, my Leader has approached the Supreme Court of India. She filed a writ petition. The matter is pending before the Supreme Court of India. Writ petition no. is 561/2008. The matter is pending. The two agreements were challenged by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu when she was the General Secretary, an ordinary person. She filed the case against these two agreements, which are unconstitutional. They are not valid. So, the matter is pending, Sir. ...*(Time-bell)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now take your seat, please.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: So, my final conclusion is, Sir,.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have heard the conclusion.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: We welcome the Budget of 2014-15. Pending arrears of aids and grants which are to be released by the Central Government may be released. Sir, the main point is the dispute of fishermen. If it is to be settled by the Government of India, retrieval of Katchatheevu is the main aspect which is to be settled.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I support that.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Thank you very much, Sir. I am once again thankful to *Dr. Puratchi Thalaivi Amma.* Thank you very much.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बजट की आलोचना करने और अपने कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दो लाइनें पढ़कर अपनी बात शुरू करूंगा,

'अच्छे दिनों का नाम न अब लीजिए जनाब,
अच्छे दिनों के नाम से अब डरने लगे हैं लोग।'

माननीय वित्त मंत्री जी सदन में नहीं हैं, हो सकता है किसी आवश्यक कार्य से गए हों। वे हमारे बड़े भाई हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं। उनमें शालीनता है, सादगी है, व्यवहार कुशलता है, वाकपटुता और योग्यता है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी आपने बजट प्रस्तुत करने के बाद, उस पर मीडिया के कमेंट्स पढ़े होते, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर अखबारों ने लिखा, 'चिदम्बरम के बजट पर आर.एस.एस. की लिपिस्टिक।' मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि न जाने इस सरकार को क्या हो गया है? चुनाव से पहले माननीय मोदी जी ने बहुत से दिवा स्वप्न दिखाए थे और ऐसा लगा था कि "राम राज" पूरा आ ही जाएगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक टिटहरी चिड़िया होती है। वह जब रात को सोती है, तो दोनों पैर ऊपर कर लेती है। उसको यह गलतफहमी होती है कि आसमान को उसने अपने दोनों पैरों से रोक लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप लोगों को भी तो ऐसी गलतफहमी नहीं हो गयी है। आपने अच्छे दिन की या और जो भी बातें कही थीं, आप अगर आज जनता के बीच में जाकर उनके कमेंट्स सुनें, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि भारी मेजॉरिटी आने के बाद भी इतने सारे एडवर्स कमेंट्स आएंगे।

आपने इस बजट में नया क्या दिया है? गरीबों को, देश को क्या दिया है? जो देश की मानसिकता है, जो देश के लोगों की सोच है, उनकी जरूरत है, वह इस बजट में कहां दिखायी देती है? आपकी सरकार पर तो यही एक आरोप है कि यह बड़े लोगों की सरकार है। आप कानून व्यवस्था की स्थिति को देखें। अभी सवेरे ही जिक्र हो रहा था। पहली बात यह कि सरकार द्वारा प्रायोजित मीडिया ने ऐसे दिखाया जैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। यह तो अच्छा हुआ कि हमारे एक साथी ने प्रश्न किया और सरकार का जवाब आया। माननीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, मैं उस समय ऊर्जा मंत्री था। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने अपने उत्तर में पूरे देश से संबंधित वर्ष 2013 तक के आंकड़े दिए हैं। उन आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है, महाराष्ट्र की खराब है और राजस्थान की खराब है। इनमें दो जगह आपकी सरकारें हैं और एक राज्य में कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में हारी सरकार है, लेकिन आप खुद ही बता रहे हैं। महोदय, मैंने इसलिए यह बात सदन में रखी कि कम-से-कम इस सदन के माध्यम से देश की जनता के बीच यह संदेश तो जाएगा कि मीडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को जो नक्शा दिखाया जा रहा है, उस नक्शे की सत्यता तो देश के सामने आनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी को यहां खड़े होकर कहना चाहिए। आपने देश में इतने कड़े कानून बनाए -निर्भया कांड के बाद आपने बहुत सख्त कानून बनाया। उसे आप जल्दी-जल्दी में लाए, लेकिन क्या देश में रेप के केसेज रुक गए? क्या

देश में अपराध रुक गए? हरदम मैंने यही कहा कि कानून बनाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, कानून बड़े सोच-समझकर और विचार-विमश के बाद बनाना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी में कानून बना दिया, जैसे अब देश में कभी रेप नहीं होंगे। आपने जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड दिया है, उसके अनुसार विश्व में अगर सबसे ज्यादा बलात्कार कहीं हो रहे हैं, तो वे अमरीका में हो रहे हैं। नंबर एक पर अमरीका है, नंबर दो पर ब्राजील, नंबर तीन पर इंग्लैड और हिन्दुस्तान दोनों आते हैं। जो विकसित देश है, जो एडवांस हैं, जहां फ्री सेक्स है, वहां पर जब यह हाल है, तो हमें अपने देश की मानसिकता पर सोचना पड़ेगा, अपनी सामाजिक सोच पर सोंचना पड़ेगा और जब तक इनके बारे में सोच कर और इन चीजों को जोड़ कर हम इस देश में एक अच्छा कानून नहीं बनाएंगे, तो तब तक आप यह मत सोचिए कि देश से अपराध समाप्त हो जाएंगे, या अपराधी समाप्त हो जाएंगे।

माननीय उपसभापति जी, इस देश की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसके लिए बजट में कोई प्रोविजन ही नहीं है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर किसी ने नहीं सोचा। मुझे याद है, आदरणीय अटल जी जब इस देश के प्रधान मंत्री थे, एन.डी.ए. की सरकार थी, तो अटल जी ने देश की आबादी पर विचार-विमश करने के लिए एक हजार लोगों की कमेटी बन गई थी। मैं समझ गया था कि इसकी बैठक कभी हो नहीं सकती और उस कमेटी की कभी कोई बैठक नहीं हुई। हम कहते हैं कि आप पहल कीजिए। आपको पहल करने में क्या दिक्कत होगी? हम लोगों पर तो आप तुष्टीकरण का आरोप लगा देते हैं। चाहे हमारी पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, जिनको हम सेक्यूलर कहते हैं, रोज उन पर आप तुष्टीकरण का आरोप लगा देते हैं। चलिए, आप ही शुरुआत करिए। अगर देश की बढ़ती हुई आबादी को हमने नहीं रोका, तो इस देश के लिए जो आप सोने की चिड़िया की सोच रख रहे हैं, जो रामराज्य की सोच रहे हैं, वह कभी संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कल राम गोपाल जी रेल बजट पर बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं गांरटी देता हूं, मैं चैलेन्ज करता हूं कि अगले बीस साल तक इस देश में आप बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि चाहे हम आएं, या आप आएं, वहां कोई भी बैठे, इस देश की बेसिक समस्या का समाधान होना चाहिए। मैंने आज सुबह एक क्वैश्चन पूछा था कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का समाधान कैसे करेंगे? क्या बढ़ती आबादी का मुख्य कारण गरीबी, मजदूरों में जागरूकता की कमी है? कहा गया कि देश भर के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। अब जो गरीब है, वह कितना इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया को देखता है, या पढ़ता है। चलिए, आप एक घोषणा करिए, सबसे सहयोग मांगिए। आज पूरा देश चिंतित है। ऐसा नहीं है कि हम वोटों की राजनीति कर रहे हैं। अगर देश नहीं है, तो वोट किसका है? इस पर आप चिंता तो करें। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, अभी मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि अपने जवाब में वे जरूर बताएं कि बढ़ती हुई आबादी के लिए उन्होंने क्या किया? मैंने कहा था, यह सही है कि सरकार को बनाने में देश के सारे पूंजीपति एक-साथ हो गए हैं। पाला इन्होंने, पलायन उधर कर गए। ...(**व्यवधान**)... यह सही है, पाला इन्होंने। एक जमाने में पेट्रोलियम पॉलिसी देश के बहुत बड़े पूंजीपति के कहने से बनती थी। एक पेट्रोलियम मंत्री इसलिए हटा दिए गए, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ गए होंगे मैं किसका कह रहा हूं, और

[श्री नरेश अग्रवाल]

देश का पेट्रोलियम सेक्रेटरी इसलिए बदल दिया गया, क्योंकि उनके हित की बात नहीं हो रही थी। आज क्या है? चुनाव में भी यही बात थी। अगर इसमें सत्यता नहीं है, तो के.जी. सिक्स बेसिन पर निर्णय क्यों नहीं होता? आप घोषणा कर दीजिए। अगर और कोई होता, वह एग्रीमेंट तोड़ देता, सरकार एग्रीमेंट समाप्त कर देती, लेकिन बड़े पूंजीपति का मामला है। कैसे उसे तोड़े? आप चार डॉलर का आठ डॉलर करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, इस पर आप घोषणा कर दीजिए। उससे साफ-साफ पता लग जाएगा। वे अड़े हुए हैं कि 2012 से बढ़े हुए रेट होने चाहिए, रंगराजन कमेटी ने कहा है कि 2014 से बढ़े हुए रेट होने चाहिए और सरकार में कोई तय नहीं कर पा रहा है। लड्डू भी खाना चाहते हैं, लेकिन मुंह खोल नहीं रहे हैं। अपने मुंह खोलिए, अगर लड्डू खाना है। अगर उनकी मदद नहीं करनी है तो साफ-साफ कहिए कि हम देश के लोगों के हित में हैं। आप नही बोल रहे हैं। अभी अखबार में आया कि सिलेण्डर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और खाद से सब्सिडी हटाने की बात हो रही है। मैं तो चाहूंगा कि आप इस बारे में विश्वास दिखाइए। यह नया कंसेप्ट हो गया है, पहले जब देश का बजट पेश होता था, तो हर साल 25 फरवरी को रेलवे का बजट और 28 फरवरी को आम बजट पेश होता था। जिस दिन देश का बजट पेश होता था, हिन्दुस्तान भर देखता था कि हमें एक साल के लिए अपने घर की रोजी-रोटी कैसे चलानी है? उस दिन जो तय हो जाता था, जो घोषणा होती थी, वह एक साल तक रहती थी, लेकिन आज तो कॉन्सेप्ट नया हो गया है कि बजट में कोई टैक्स नहीं, उसके बाद टैक्स। बजट में मीठी-मीठी घोषणा, उसके बाद वह घोषणा वापस। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी आज इस बात की घोषणा करें, फिर से उस कॉन्सेप्ट को लाएं, जो देश के लोगों ने सरकार से चाहा था, कि हम आज जो घोषणा करेंगे, जो छूट देंगे, वह 27 फरवरी, 2015 तक लागू रहेगी, बीच में बदली नहीं जाएगी। आप जनता के सामने यह घोषणा कीजिए। आप इतने वायदे करके आए हैं, इतनी बातें करके आए हैं, तो फिर आपको यह करने में क्या दिक्कत है? मैं तो चाहता हूं कि आपको इसे करना चाहिए।

जब आप इधर बैठे थे, एफ.डी.आई. का बड़ा विरोध कर रहे थे, हमारे साथ आप भी थे। हम तो सदन का बायकॉट भी कर गए थे, कुछ दिनों तक सदन चलने नहीं दिया था। अब तो हर जगह एफ.डी.आई. की बात हो रही है। अब तो आपने सबमें 25-26 परसेंट से बढ़ाकर 49 परसेंट कर दिया, लेकिन मृगमरीचिका पर आप कब तक चलेंगे? अगर आपको एफ.डी.आई. वाकयी में लाना है, इस देश में नई टेक्नीक लानी है, तो फिर 49 परसेंट की लिमिट पर आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी टेक्नीशियन, जब तक वह 60-70 परसेंट से ऊपर नहीं ले लेगा, जब तक वह अपना वर्चस्व नहीं ले लेगा, तब तक वह एफ.डी.आई. नहीं लाएगा। फिर आपको थोड़े दिनों बाद यही कहना पड़ेगा कि हम रक्षा के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, ऑयल के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में एफ.डी.आई. ला रहे हैं। तो अगर लाना है, तो ढंग से एफ.डी.आई लाइए। ऐसे तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कह रखा है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि न फुटकर, न थोक, हम दोनों में एफ.डी.आई. उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको देश में लाना है, आप लोगों को सपना दिखा रहे हैं, तो

सही सपना दिखाइए। अब आप सोचें कि फ्रांस विमान बनाने की या वैपन बनाने की अपनी टेक्नीक ले आएगा या इजराइल अपनी टेक्नीक ले आएगा। वह 49 परसेंट रुपया देगा और मालिक आप रहेंगे, वह नौकर बना रहेगा, तो कौन अपनी टेक्नीक देगा? जब तक 51 परसेंट उसका शेयर नहीं होगा, जब तक वह उसका सी.एम.डी. नहीं बनेगा, उसका मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक वह क्यों अपनी टेक्नीक लाएगा? मैं चाहूंगा कि आपके उत्तर में यह बात भी जरा स्पष्ट हो जाए।

श्रीमन्, हम बहुत दिनों से पी.पी.पी. के बारे में सुन रहे हैं। जितने भी आपने पी.पी.पी. के प्रोजेक्ट्स आज तक किए हैं, क्या उनमें कहीं भी आपको लाभ हुआ है? मैं उदाहरण के लिए दो प्रोजेक्ट्स के बारे में कह रहा हूं। रेलवे में आपने पी.पी. किया, करीब आठ परियोजनाएं आपने लागू कीं, जो लगभग 2,167 करोड़ रुपए की थीं, जिसमें अब तक परियोजना वालों ने 128 करोड़ रुपए का फायदा ले लिया, लेकिन आपकी परियोजना पूरी नहीं की, तो आपको क्या फायदा, हुआ? MIAL पर तो जो सबसे बड़ी आपत्ति की, MIAL जो मुम्बई का एयरपोर्ट आपने दिया है। - दिल्ली का भी दिया, मुम्बई का भी दे दिया - तो मुम्बई के एयरपोर्ट पर 2013 के दौरान MIAL को 2,857 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जबकि उन्होंने सिर्फ 888 करोड़ रुपए निवेश किए। अगर इतने रुपए पर इतना प्रॉफिट देकर आप पी.पी.पी. लाना चाहते हैं, तो फिर हमारे आरोपों में कहां कोई खराबी है? हमारे आरोप कहां से गलत हैं,? मैं तो कहता हूं कि यह पूंजीपतियों की सरकार है, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है। महंगाई की बात आई, आपने कहा, हम पूरे देश में 3/7 लागू करेंगे, देश में छापे मारेंगे, लेकिन आप छापे नहीं मार सकते क्योंकि वही व्यापारी तो आपका वोटर है, जिस पर छापे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे याद है, आपके कई एम.पी. चुनाव से पहले यह वादा करते थे कि अगर केन्द्र में हमारी सरकार बन जाएगी, तो 3/7 हम समाप्त कर देंगे। क्या आप 3/7 समाप्त करने की सोच रहे हैं, इतना ही बता दीजिए। या तो 3/7 तेजी से लागू कर दीजिए या 3/7 समाप्त कर दीजिए, क्योंकि अगर कालाबाजारी, होर्डिंग को रोकना चाहते हैं, तो 3/7 को लागू रखें और नहीं रोकना चाहते हैं, तो 3/7 को आप समाप्त कर दीजिए, जिससे आपका वोटर भी खुश हो जाए। आप बीच की दुविधा में मत रहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। न आया, न गया, इसमें मत रहिए। जो करना है, वह कीजिए, डंके की चोट पर कीजिए, जैसे हमारे नेता मुलायम सिंह जी, जो कहते हैं, वह कर देते हैं। उसमें फिर वे यह नहीं देखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप डंके की चोट पर कीजिए, आपको कौन मना कर रहा है?

निर्मला सीतारमण जी, आप यहां बैठी हैं। आपने कंपनी लॉ में एक अमेंडमेंट कर दिया। अगर दो कम्पनियों में एक ही व्यक्ति डायरेक्टर है, तो वह एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में रुपए ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका क्या फायदा हुआ? अगर हम ट्रांसफर करना चाहें, तो पहले तीसरी कम्पनी को रुपए दें और उस तीसरी कम्पनी से रुपए लेकर फिर अपनी दूसरी कम्पनी में लाएं। इस अमेंडमेंट का क्या फायदा हुआ, यह मैं नहीं समझ पाया हूं। आप इसको देख लीजिए और अगर इस पर पुनर्विचार कर लें तो अच्छा होगा। महोदय, इस देश में सेबी आया। कहा गया

[श्री नरेश अग्रवाल]

कि सेबी आएगा तो रेग्युलेट करेगा, देश में सारी पोंजी स्कीम्स खत्म हो जाएंगी। जो तमाम लोग छोटे लोगों का रुपया मार ले जाते हैं, उनको सेबी रेग्युलेट करेगा। करीब सौ कम्पनियां ऐसी हैं, जिन पर सेबी ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। आप कहें तो मैं उनके नाम दे दूं जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए का गबन किया है। इन्होंने सेबी को पॉवर देने की बात इसलिए की क्योंकि देश के एक बड़े भारी पूंजीपति को इन्हें जेल में डालना था। ये कांग्रेस वाले, इनके यहां से फरमान हुआ, उस समय के वित्त मंत्री जी उस फरमान को लेकर चल दिए और सेबी को इतनी बड़ी पॉवर देने लगे। विश्व में किसी भी रेग्युलेटर को इतनी बड़ी पॉवर नहीं थी कि अपना कोड बनाए, जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे सजा दे दे, यानी सब काम सेबी करे। हम सब लोगों ने फाइनेंस कमेटी में उसका विरोध किया। हम लोगों ने कहा कि पहले पूरे वर्ल्ड में, जहां भी रेग्युलेटर्स हैं, कम से कम उनकी पॉवर्स को तो देख लीजिए। आज भी शारदा ग्रुप है, अलकेमिस्ट है, रोज वैली है, तमाम ऐसी कम्पनियां हैं, जिन्होंने जनता का हजारों करोड़ रुपया मार लिया, लेकिन आप चुप हैं, आपका सेबी कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि सरकारी दबाव में कोई कार्यवाही नही हो रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आप एक नया नारा लेकर आए- "कोऑपरेटिव फैडरेलिज्म"। बड़ी जोर-शोर से नारा दिया, 'सबका सहयोग लेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे।' मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, वे अभी ब्रिक्स सम्मलेन में भी गयी थीं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आपने बजट बनाया, उस समय देश के सारे उद्योगपतियों को आपने बुलाया, लेबर लीडर्स को बुलाया, इकोनॉमिस्ट्स को बुलाया। अगर आप कोऑपरेटिव फैडरेलिज्म की बात कर रही हैं तो क्या आपको देश के मुख्य मंत्रियों को नहीं बुलाया चाहिए था? आखिर हमारे राज्यों से आप आमदनी लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी आमदनी राज्यों पर निर्भर है। आपने एक बार भी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठकर बात नहीं की कि हम कैसा बजट बनाएं, किस राज्य को क्या जरूरत है? आपने देश के एक किसान से बात नहीं की और आप कहते हैं कि हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इस देश की अर्थव्यवस्था आज तक भी कृषि पर आधारित है, लेकिन आपने एक किसान को बुलाना उचित नहीं समझा। सारे उद्योगपति, सारे लेबर लीडर्स, सारे इकोनॉमिस्ट्स तो आपने बुला लिए, लेकिन अर्थव्यवस्था की रीढ़ को आपने छोड़ दिया। हम कैसे मान लें कि आपका यह नारा बहुत अच्छा है, आप किसानों की मदद करना चाहते हैं और आप राज्यों को साथ लेकर चलना चाहते हैं? रेलवे बजट में भी यही हुआ-किसी भी राज्य को नहीं बुलाया गया। हमने तो कहा था, 1000 किलोमीटर लम्बा उत्तर प्रदेश है, 22 करोड़ की हमारी आबादी है, रेल ने हमें क्या दिया? कल रेल मंत्री जी ने अपने जवाब में उत्तर प्रदेश का नाम लेना तक उचित नहीं समझा। या तो प्रधान मंत्री जी में और उनमें झगड़ा है, बी.जे.पी. की आंतरिक कलह है। प्रधान मंत्री अब उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री है, प्रधान मंत्री गुजरात के नहीं हैं। लेकिन उन्होंने एक बार भी उत्तर प्रदेश का नाम लेना अपनी तौहीन समझा। अगर वे उत्तर प्रदेश का नाम ले लेते तो लगता कि रेल बजट में उत्तर प्रदेश की भी कोई बात हुई है। उन्होंने रेल बजट में उत्तर प्रदेश की पूरी उपेक्षा की जैसे इस बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है। मैंने उस दिन स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि एम्स जैसा संस्थान उत्तर प्रदेश को मिला? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक नहीं मिला, रायबरेली को पहले मिल चुका है। महोदय, नेशनल हाईवेज को देख लीजिए। सबसे कम नेशनल हाईवेज उत्तर प्रदेश में हैं और

सबसे अधिक नेशनल हाइवेज साउथ में हैं। क्यों उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हो रही है? यही मैं कह रहा हूं। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, देश में जितने प्रधानमंत्री बने, 90 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के हैं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हो रही है। हमने तो कहा कि उत्तर प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देने की बात भी नहीं की। आप देते, मैंने तो कहा, हम मानक में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश एक गरीब प्रदेश है, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश को कहां प्राथमिकता पर लिया? बनारस में केवल एक मिनी सचिवालय खोल देने से उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर नहीं हो जाएगी, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो जाएगा। गंगा के साफ हो जाने से उत्तर प्रदेश की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। आपने इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कल्पना के विपरीत 73 सीटें जीतीं, उस उत्तर प्रदेश की आप ऐसे उपेक्षा करेंगे? आपके यहां यह झगड़ा चल रहा है कि नम्बर दो कौन होगा? अब नम्बर दो कौन होगा, यह तो पता नहीं है, ...(**व्यवधान**)... चलो, हमारी सरकार के अटॉर्नी जनरल मैत्रेयन जी हैं, इन्होंने सैटल कर दिया होगा। हम इनको सरकार का अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ...(**व्यवधान**)... कि सरकार में जो झगड़ा हो मैत्रेयन जी ठीक कर देंगे। ...(**व्यवधान**)... हम तो कहेंगे कि यहां हमारी बड़ी बहन बैठी हैं, ये बता दें कि आपकी पार्टी में नम्बर दो कौन है? आप नहीं बता पाएंगी, इसलिए हम आपको विवाद में नहीं डालना चाहते। ...(**व्यवधान**)... आप हमारी इतनी प्यारी बहन हैं, हम आपको विवाद में नहीं डालना चाहते। यदि और कोई हो, तो यह बता दे। देश में सूखा है और सरकार में झगड़ा है कि नम्बर दो कौन है। मैं तो कहूंगा कि आज घोषित कर दीजिए कि सरकार में नम्बर दो कौन है और नम्बर तीन कौन है? वैसे दो नम्बरी होता बड़ा खराब है। हम लोग दो नम्बरी को अच्छा नहीं मानते। ...(**व्यवधान**)... अब इसमें झगड़ा है। हमारे नाम राशि कुछ बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश) : ट्रक के पीठ लिखा होता है, ''जल मत बराबरी कर। खुदा तुझे भी देगा इंतजार कर।''

श्री नरेश अग्रवाल : यही सीख आप अपने ऊपर लीजिएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री अनिल माधव दवे : हमको तो दे दिया। ...(**व्यवधान**)... हमको तो छप्पर फाड़कर दे दिया। इतना दिया है कि झोली में भी नहीं समा रहा है।

श्री नरेश अग्रवाल : काले धन के मुद्दे को बड़े जोर-शोर से उठाया गया। यह कहा गया कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम स्विटजरलैंड से सारी ब्लैक मनी ले आएंगे और देश की सारी ब्लैक मनी निकाल लेंगे। बाबा रामदेव ने भी बी.जे.पी. के बिहाफ पर ब्लैक मनी का नारा दिया था। हम लोग तो यह समझ रहे थे कि सरकार आएगी और तुरंत काला धन वापस आएगा।

मैं आज ही पढ़ रहा था कि स्विटजरलैंड इस बात पर राजी हुआ है कि आप अपनी एक टीम भेज दीजिए, हम वार्ता करेंगे। अभी स्विटजरलैंड इस बात पर राजी नहीं है कि हम आपको नाम देंगे, क्योंकि स्विटजरलैंड आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। स्विटजरलैंड का बैंक ही तो मुख्य धंधा है। स्विटजरलैंड की पूरी इकोनॉमी बैंक पर चल रही है। कोई देश आपके लिए

[श्री नरेश अग्रवाल]

अपनी इकोनॉमी खत्म कर देगा? आप कुछ भी कहते रहें। मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने स्विटजरलैंड में काला धन जमा किया है, उनके खिलाफ फ्रुटफुल कार्रवाई कीजिए। कल वित्त मंत्री जी इनकम टैक्स आर्फिसस के सम्मेलन में गए थे। उन्होंने कहा कि देश का भी काला धन निकालों। हमारे देश में कितने परसेंट लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं? तीन या चार परसेंट से ऊपर देश का आम नागरिक इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, सात-आठ परसेंट आपके कर्मचारी इनकम टैक्स दे रहे हैं। आप देश का इनकम टैक्स तीन परसेंट से ऊपर नहीं बढ़ा पाए हैं, आप क्या बात करते हैं? वैसे तो चिदम्बरम जी ने एक बार लोगों से कह दिया था कि जितना भी काला धन दिखाओगे, हम उसके बारे में नहीं पूछेंगे और तीस परसेंट टैक्स ले लेंगे, लेकिन उससे आपकी जो व्हाइट मनी बनेगी, उसको इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में लगाइए। आप क्यों नहीं इस प्रकार की डिक्लेयर्ड स्कीम ले आते? आप एक बार ऐसी डिक्लेयर्ड स्कीम ले आइए। आप एक बार फिर पूरे देश को मौका दे दीजिए, क्योंकि कहा जाता है जितनी व्हाइट मनी उससे तीन टाइम ब्लैक मनी मार्केट में है। उस ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए यह स्कीम क्यों नहीं लाते हैं? आप कितने छापे मारेंगे? आप बड़े-बड़े लोगों के यहां तो छापा मार देंगे, लेकिन सभी जगह तो छापा नहीं मारेंगे। आप खुद अपने जवाब में बता दीजिए कि इस देश में कितने परसेंट लोग इनकम टैक्स देते हैं? आपने कहा है कि हमने इनकम टैक्स पर पचास हजार की छूट दे दी है, यह तो 'ऊंट के मुंह में जीरा' के बराबर है। आपकी यह छूट कितने लोगों पर लागू है, इनकम टैक्स से क्या फायदा हुआ? अगर आपको वाकई में देनी थी, तो आप किसान के लिए कोई घोषणा करते। आज सुबह लोग पूछ रहे थे कि आपका एन.पी.ए. कितना है? इस देश में किसान, गरीबी और महंगाई, तीन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सरकार ने इनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं की। अमरीका में भी किसान को सब्सिडी दी जाती है, आस्ट्रेलिया में भी किसान को सब्सिडी दी जाती है। जो बड़े मुल्क हैं, उन मुल्कों में अमीर किसान हैं और हमारे मुल्के में गरीब किसान हैं। हमने कहा है कि आप उस अमीर किसान को छोड़ दीजिए, गरीब किसान की बात कीजिए। आपका एन.पी.ए. बढ़कर चार परसेंट हो गया। यह दो परसेंट होना चाहिए। आप अपनी इक्विटी पूरी करने के लिए हर बार सरकार की तरफ से बैंकों को मदद दे रहे हैं। बैंकों के सी.एम.डी. राजा हैं, वे जैसे चाहे बैंक से धन खर्च करें, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। वे जिस पर खुश हो गए, उसको बिना कोई गांरटी लिए चाहे जितना धन दे दें। एन.पी.ए. बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपके सामने एक लिस्ट रख रहा हूं, जो लिस्ट आई है, उसमें लगभग 57 हजार करोड़ रुपये बाकी हैं। बैड लोन्स की जो लिस्ट निकली है, उनमें जो कंपनियां हैं, उनमें किंगफिशर, ₹ 4,022 crore, Winsome Diamond ₹ 3,243 crore, Electrotherm India ₹ 2,653 crore, Corporate Power ₹ 2,487 crore, Sterling Biotech ₹ 2,031, Forever Precious ₹ 1,754 crore, KS Oil ₹ 1,705 crore और Zoom Developes ₹ 1, 419 crore हैं। ये आपके बड़े डिफाल्टर्स हैं। अगर किसान पर 1000 रुपये भी बाकी रह जाते, तो बेचारे की आर.सी. तहसील में चली गई होती, लाल शब्दों में मोटा-मोटा नाम लिख दिया जाता और शाम को उसे पकड़कर चौदह दिन के लिए तहसील की जेल में डाल दिया जाता। क्या इनके लिए यह कानून नहीं है? क्या इस देश में दो कानून हैं? क्या बड़े लोगों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए अलग कानून है? मैंने जो

किसान की बात उठाई है, मैं पूछता हूं कि सूखा पड़ रहा है, इसके लिए आपने क्या घोषणा की है? थोड़े दिनों में बाढ़ आने की स्थिति हो जाएगी। जब बाढ़ आने की स्थिति होगी, तो आप क्या मदद देंगे? आपने खुद अपने घोषणापत्र में किसान की उपज के मूल्य के बारे में कहा है। आप हर जगह कहते थे यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो किसान का जो उपज मूल्य होगा, हम उसका ड्योढ़ा मूल्य घोषित करेंगे, जिससे किसान अच्छा जीवन जी सके। अगर उसका उपज मूल्य 1000 रुपये आएगा, तो क्या आप 1500 रुपये की घोषणा करेंगे? आपने कितना मूल्य बढ़ाया है? आपने धान में पचास-साठ रुपये बढ़ा दिए, पर क्या यह किसान की लागत के बराबर भी है? किसान की मार्किटिंग के लिए क्या व्यवस्था बनी हुई है? किसान अपनी फसल उपजाता है, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। अगर मंडी में बिचौलिये न हो, तो किसान को खाना खाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, उसका ट्रैक्टर इकोनॉमिकल नहीं हैं, जोत छोटी हो गई। अगर किसान एक ट्रैक्टर खरीद ले, उससे लोडिंग/अनलोडिंग न करे, सामान न ढोए तो केवल एग्रीकल्चर के माध्यम से वह उसकी किस्त भी अदा नहीं कर सकता है। आप इस देश के किसान को क्या दे रहे हैं? मैंने आपसे कहा है कि आप छोटी जोत खत्म करने के लिए कानून बनाइए, जिससे अलाभकारी जोत न हो, खेती की तरफ लोगों की रुचि समाप्त न हो। देश ने आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, क्योंकि आजादी के बाद तीन बार परिवार बालिग हो गए। एक परिवार में तीन-तीन बार बंटवारा हो गया, जिससे जोत बहुत छोटी हो गई। आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं? आप किसान में रुचि पैदा क्यों नहीं करते हैं? क्यों गांव का आदमी शहर की तरफ भाग रहा है? अगर यही स्थिति बनी रही और आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम टूट गया, तो कृषि आधारित आपकी अर्थ नीति भी टूट जाएगी। यदि आपकी व्यवस्था टूट गई, आमदनी टूट गई, तो देश का क्या होगा? श्रीमन्, देश प्राथमिकता है। अगर इस देश के किसान, मजदूर और गरीब की बात नहीं हुई, तो व्यर्थ है। आज हम सभी मानते हैं कि यह प्राथमिकता है। आपने गरीब की परिभाषा बताने के लिए चार कमीशन बना दिए। सक्सेना कमीशन, सेनगुप्ता कमीशन, तेंदुलकर कमीशन, इसके बाद रंगराजन कमीशन। सिर्फ वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए आपने इन कमीशन्स को बिठाकर हिन्दुस्तान के गरीबों की संख्या कम ही है। मजाक तो तब हुआ, जब तेन्दुलकर कमीशन ने गांव में 18-20 रुपये और शहर में 30 रुपये पाने वाले व्यक्ति को परिभाषित किया। यह मजाक इनकी सरकार ने किया था और फिर आपकी सरकार में रंगराजन जी ने फिर से यह मजाक कर दिया कि 33 रुपये, 47 रुपये पाने वाला व्यक्ति इस देश में गरीब नहीं रहेगा। हमने तो रंगराजन जी से कहा था कि हम आपको अपनी जेब से सौ रुपये देते हैं, आप गांव में एक रात रहकर दों टाइम खाना खाकर आओ, तो मैं समझूंगा कि आपने एक सही रिपोर्ट दी है। लेकिन नहीं, चूंकि इनको वर्ल्ड बैंक और विश्व के अन्य बैंक्स को दिखाना है कि हमने आपसे गरीबी हटाने के लिए, हिन्दुस्तान की डेवलपमेंट के लिए जो लोन लिया, उस लोन के माध्यम से हमने देश में गरीबी घटा टी। इन फर्जी आंकड़ों से कोई फायदा नहीं होगा। आपको सत्यता पर चलना होगा। अगर आपने इस देश की गरीबी और बेरोजगारी पर विचार नहीं किया, यदि आपने सही मायनों में, सत्यता से इस देश के डेवलपमेंट की बात नहीं की, तो सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर देश गरीब रहा, देश का कुछ

[श्री नरेश अग्रवाल]

नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? हम राजनीति में तनख्वाह लेने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने विचार देकर देश की समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am also enjoying your speech, लेकिन मैं क्या करूं? आप बोर्ड की तरफ देखिए, आपका टाइम खत्म हो गया है। You can take two or three minutes more.

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन्, हम महंगाई की बात कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में लिखा जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक कम हुआ है। हमने महंगाई पर पर भी रोक लगा दी और अब जो फुटकर सूचकांक है, हम उसे 13 से 9 परसेंट पर ले आए। हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि 9 परसेंट या 13 परसेंट क्या है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि टमाटर के दाम 300 परसेंट बढ़ और प्याज के दाम 50 परसेंट बढ़ गए। आप सब भी बैठे हुए हैं। तरुण भाई, अगर हम गलत बात कह रहें हैं, तो आप हमारी बात काट दीजिएगा। मैं तो सारे अखबारों में आज सवेरे पढ़ रहा था कि टमाटर के दाम 300 परसेंट और प्याज के दाम 50 परसेंट बढ़ गए। एक जमाने में जब हम लोग सब्जी खरीदते थे, तो हरी मिर्च, पुदीना और धनिया मुफ्त दे दी जाती थी। जब हम लोग छोटे थे, तो हम भी सब्जी लेने बाजार जाते थे, तो वह साथ में मुफ्त दे देता था। श्रीमन्, अब मुफ्त तो छोड़िए, पहले तो 100 रुपए में एक महीने की सब्जी ले आते थे, अब तो 1,000 रुपए में एक दिन की सब्जी नहीं मिल रही है। आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि देश में महंगाई है। आपने 500 करोड़ रुपए का बजट रख दिया है कि इससे महंगाई दूर करेंगे, लेकिन 500 करोड़ रुपए में आप महंगाई कैसे दूर करेंगे? आप कहां पर 500 करोड़ रुपए लगाएंगे? प्याज की सब्सिडी में लगाएंगे, टमाटर में लगाएंगे, किसान के बीज में लगाएंगे, खाद में लगाएंगे या अन्य सब्जियों में लगाएंगे? आटा, दाल, घी - सभी चीजें तो आदमी की जरूरत होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप 500 करोड़ रुपए का बाइफरकेशन करके बता दें, जिससे पूरा देश सुने कि आपने जो 500 करोड़ रुपए महंगाई रोकने के लिए रखे हैं, क्या आपने वे 500 करोड़ रुपये कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए रखे हैं, जो महंगाई को रोकेंगे? आपने 500 करोड़ रुपए इस देश में महंगाई रोकने के लिए रखे हैं। लोगों के दिमाग में एक शंका है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा, कौन महंगाई रोकने जाएगा, आप किसको इस्तेमाल करेंगे, अगर राज्य सरकारों को देंगे, तो कितने-कितने रुपए राज्य सरकारों के जिम्मे पड़ेंगे, अगर एड्वर्टाइजमेंट के लिए देंगे, तो एड्वर्टाइजमेंट इतना महंगा हो गया है कि उसमें 500 करोड़ रुपए का पता नहीं चलेगा। यह 500 करोड़ रुपए आप कैसे खर्च करेंगे? महंगाई कैसे रुकेगी? खाली आंकड़ों पर मत जाइए। अभी कुछ दिन पहले इस सदन में महंगाई पर चर्चा हो रही थी, तो सारे सदन ने उस पर चिन्ता व्यक्त की थी, चाहे इधर के सदस्य हों, चाहे उधर के। जो चीजे सही है, सब लोग बोलते हैं। पूरे सदन ने चिन्ता व्यक्त की थी। यह मत सोचिए कि महंगाई से आपके नम्बर कम नहीं हो रहे हैं। आप महंगाई की आलोचना करके यहां आए हैं। यही ठीक है कि नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ लोग नहीं सुनना चाहते थे। हम लोग खुद चुनाव हारे। चुनाव हारने के बाद हम जान गए थे कि जनता का मूड क्या है, लेकिन जब आपकी आलोचना शुरू हुई, तो हम लोगों की हिम्मत बनी कि चलिए, कहीं पर तो शुरुआत हुई।

श्री उपसभापति : नरेश जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल : मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं।

हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, कही भी मौका मिले, हम राजनीतिक स्टेट हैं। आखिर नरेन्द्र मोदी जी को भी प्रधान मंत्री बनने के लिए गुजरात से उत्तर प्रदेश आना पड़ा, क्योंकि वे जानते थे अगर वे गुजरात से जीतेंगे, तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बनते हैं। हमने हरदम कहा है कि गुजरात सफल व्यापारी दे सकता है, लेकिन सफल नेता उत्तर प्रदेश ही देगा। यह मान कर चलिएगा कि इस देश में अगर कोई सफल राजनेता पैदा करता है, तो वह उत्तर प्रदेश पैदा करता है। राजनीति की दिशा अगर कोई देता है, तो वह उत्तर प्रदेश देता है। इसलिए सब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के होते हैं। पिछली सरकार में मनमोहन सिंह जी तो लिखा-पढ़ी में थे, रिमोट तो दस जनपथ में था। वह भी उत्तर प्रदेश से था। मैं तो बड़ा साफ कहता था कि रिमोट दस जनपथ में था। आज कही-न-कहीं रिमोट है। आर.एस.एस. का कैंप झंडेवालन में है, वहां पर रिमोट है।....**समय की घंटी**...

चलिए, मेरे बड़े भाई आ गए। मुझे अभी बहुत कुछ कहना था, लेकिन अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय जेटली जी, आप जब इधर बैठे थे, तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखता था। यद्यपि मुझे भी राजनीति में 35 साल हो गए हैं, यह ठीक है कि मैं लोअर हाउस में था, विधान सभा में था, मंत्री रहा। वहां राजनीतिक कलाबाजी भी सीखी, वहां आंकड़ों की जादूगरी भी सीखी। पक्ष में कैसा बोला जाए, विपक्ष में कैसा बोला जाए, सरकार कैसे बनाएं, कैसे बिगाड़ें, यह भी हमने बहुत किया। इसकी कलाकारी भी हमने बहुत अच्छी की है। लेकिन हम सबका एक उद्देश्य है, हम एक सोच के साथ आए हैं कि अगर हमारा हिन्दुस्तान अच्छा रहेगा, तो हम सब अच्छे हैं और जीने का फायदा है, राजनीति करने का फायदा है। अगर हमारा हिन्दुस्तान अच्छा न हुआ, हम राजनीति करते रहे, तो शायद हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे यह अपील करूंगा कि मैंने बजट के प्रावधानों के बारे में जो बातें उठाई हैं, आप यहां नहीं थे, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, उन चीजों के बारे में भी सोच कर अगर आप बजट में थोड़ा बदलाव करेंगे और वाकई में देश के किसान, गरीब और इस देश में रामराज्य की कल्पना करेंगे, तो मैं आपका साथ दूंगा, अन्यथा डट कर विरोध करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI P. RAJEEVE: Mr. Deputy Chairman, Sir, we are discussing the maiden Budget of the NDA Government. In the first sentence of the Budget Speech of the hon. Finance Minister, he has used the word 'change'. But it remains as a word without any implication. We could not find any change of policies in the Budget of the NDA Government. It is as same as of the UPA Government. We have seen respected Deputy Leader of the Congress Party, Shri Anand Sharma, strongly arguing for getting the pattern of Shri Arun Jaitley's Budget.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE) in the Chair]

Sir, the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, has ascertained that this is the same pattern of his Government Budget. I quote, "This is a Budget which could have well been presented by the UPA itself." This is a comment of the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. Sir, the former Finance Minister, Shri Chidambaram, congratulated Shri Jaitley for following his own policies. And the hon. Finance Minister did not hide his awe for his predecessor with regard to fiscal consolidation.

Sir, whether this side or that side, both are actually two sides of the same coin. Then what about the main beneficiaries and their opinion? The last issue of Outlook consolidates the opinion of the corporate sector with regard to the latest Budget. Kumar Manglam Birla says, "This Budget signals to investors that India is here to do business in a stable and predictable way." What was his opinion on the 2013 Budget? It was, "Inclusive and sustainable growth." What was his opinion on 2012 Budget? It will, "Send positive signals." Then the Chairman, HDFC says about 2014, "A good beginning". About 2013 Budget, he says, "A sensible Budget." About 2012 Budget, he says, "A reasonable, equitable and balanced Budget." The Confederation of Indian Industries says about 2014 Budget, "Meets the expectations of the industry." It says about the 2013 Budget, "We welcome the Budget. It focusses on inclusive and sustainable human development." Sir, I would not like to quote all comments because of scarcity of time. The corporate world welcomes this Budget and the earlier Budgets. But what about the opinion of other organizations? INTUC, which is affiliated to Congress, was criticizing the UPA Budget; BMS which has some ideological relationship with BJP, is criticizing the Budget presented by Shri Jaitley. Sir, actually, Shri Sitaram Yechury, while participating in the debate on the President's Address, correctly stated that BJP has taken the baton in this relay from the Congress. Now they are running as fast as they can to give more concessions to the corporate and to give more sufferings to the common people of the country. That is the reality. Actually, this shrinks our concept of democracy. In democracy, in the elections, the people, the voters vote for a candidate who is representing a political party and a political party represents an ideology and policies. Now we are elected to this side or that side. Both of them are actually reflecting, actually focussing the same policies. This is the status of democracy in our country. Sir, I want to add one more thing here, which Shri Naresh has already mentioned. Shri Arun Jaitely tried to add some saffron cosmetics to the UPA Budget. The Economic Times correctly gave a good title, "A Chidambaram Budget with saffron lipstick." That we have seen in this Budget, "A Chidambaram Budget with saffron lipstick." Sir, in macro analysis, the Government policies are only contributing to deepen the economic crisis in our country. You are focusing on exports. The global meltdown is continuing. So, the international market is shrinking. Then what about the domestic

market? The purchasing power of a majority of the people is declining. It is true that the income of the super rich has increased drastically. But they are not able to purchase for themselves all these things. And they are focussing on speculative trade, currency trade, stock market or real estate. Now, this leads to deepening of the economic crisis in the country. The Prime Minister and other Ministers always talk about the Chinese model. Shri Anand Sharma mentioned about the stimulus package. What was their stimulus package? They were giving more concessions to corporates. But what is the experience with the Chinese model? They are pumping more funds into the economy. They had increased the public funding on infrastructure. But we are continuing the same fiscal policy. Jaitleyji is also trying to continue the same fiscal policy. I am totally against the fiscal deficit mantra. It is true that we should control the revenue deficit. But what about the fiscal deficit? If we are using money for infrastructure projects, it will create more employment. People will get more money and they will purchase more goods. They will go to the market and the demand will increase. Then the production should be increased. This will create more jobs and people will get more money. And this will give more momentum to the dynamics of economics. But, instead of that, if you are sticking to the fiscal deficit mantra and giving more concessions to the corporates, then, this will not help our country. You are following the failed Thittooras of where financial institutions run. Sir, while the Finance Minister was talking about the fiscal deficit, he was only confined to the expenditure side. The earlier Finance Ministers were also concentrating on only the expenditure side, cutting subsidies and cutting expenditures. How did the last UPA Government control the fiscal deficit? They had managed it by serious expenditure cuts. While we are going through the Budget Estimates, the Revised Estimates and the Actual Expenditure, we can find out big differences. Fiscal consolidation should be effected through contraction of public expenditure and not by increasing revenues, What is the present status of revenue components? As per the answer given by the former Finance Minister in this House, the uncollected tax amounts to more than ₹ 5.10 lakh crores. This is the same as that of the fiscal deficit of our country. Sir, if they had collected these tax arrears, then, there would have been no fiscal deficit. Using this fiscal deficit issue, they are going to cut subsidies and they are going to cut expenditures. Out of these uncollected tax arrears, more than ₹ 75,000 crores are undisputed tax arrears. There is no dispute on this figure. It is true that the Minister has now decided to formulate some mechanism for clearing all these things. That is a good move. But out of these, ₹ 75,000 crores are undisputed tax figures. The Prime Minister and the Finance Minister are always talking about tax terrorism, and Anand Sharmaji also mentioned about tax terrorism. I want to know what the definition of tax terrorism is and what their perspective of tax terrorism is. What does it mean? I am totally against the way they are applying it. The Tax-GDP ratio in our country is only

[Shri P. Rajeeve]

around 10 per cent. The Tax-GDP in England is 26.9 per cent. In Norway, it is 27.3 per cent. In Denmark, it is 34.1 per cent. In Belgium, it is 25.7 per cent. If we can increase one percentage of this, then, the Exchequer would get more than Rs.1.25 lakh crores. It means that if we can change our Tax GDP ratio at par with England, then, our Exchequer will get an additional tax revenue of around Rs.20 lakh crores. If we can change our tax GDP ratio at par with England, then, our exchequer would get additional tax revenue of around ₹ 20 lakhs crores. If we can change our tax GDP ratio at par with Norway, then we would get an additional ₹ 30 lakh crores as revenue. Is it tax terrorism? Then, another statement is in public domain in the Budget documents itself. Out of the 6,18,806 companies, for which the tax return you have submitted, 2,84,069 have not paid a single paise as taxes. Despite statutory tax ratio of 30 per cent, companies that made a profit greater than Rs. 500 crores at Effective Tax Rate (ETR) is only 20.97 percentage. Is it tax terrorism? Sir, regarding on-line trading, if we want something we are going to the Net, to Amazon or Flipkart. Are you charging any tax for that? Sir, coming to property tax, which includes wealth tax, immovable property tax, estate, inherited and gift tax, Jaitleyji, this property tax constitutes only 0.40 of the total tax revenue. Nirmalaji recently went to attend the BRICS Summit. In BRICS countries, the average is 4.85 per cent, in G-20 the average is 7.6 per cent. Is it tax terrorism? Following Mr. Chidambaram, Jaitleyji also...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Rajeeve, please sit down. The Finance Minister has to say something.

SHRI ARUN JAITLEY: There is one difficulty. At six o' clock there is a guillotine in the Lok Sabha. So all the Cabinet Ministers will have to be there. If the hon. Members agree, I will go there. Najmaji will go there. My colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman will be here so that the proceedings are not disturbed. So for about ten to fifteen minutes we will be without a Cabinet Minister here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay.

SHRI P. RAJEEVE: But that is not the precedence.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; you listen to me. MoS will be here.

SHRI P. RAJEEVE: At least one Cabinet Minister should be here.

SHRI ARUN JAITLEY: We can ask Najmaji to be here.

SHRI ANAND SHARMA: Dr. Najma is not a Member of the Lok Sabha. She does not have to vote.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If there is a cut motion, then, she has to be there.

SHRI ARUN JAITLEY: If there is a cut motion in her Ministry and if she is not present...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will explain. You should understand. You were also Government. If there is a cut motion, then the concerned Minister has to be there. I hope you will agree with that. MoS will be here for about fifteen to twenty minutes. All right, you both can go.

SHRI ARUN JAITLEY: Thank you. I am grateful, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now you please continue, Mr. Rajeeve.

SHRI P. RAJEEVE: Actually I am going to the main point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be recorded. Shrimati Nirmala Sitharaman is a very efficient Minister. She will take notes.

SHRI P. RAJEEVE: Yes, she is a dynamic Minister. But, Sir, Shri Anand Sharma mentioned about the retrospective taxation. I am surprised. When Mr. Pranab Mukherjee was Finance Minister -- and who is now the hon. President of India -- at that time both Houses passed the Finance Bill along with a clause for retrospective taxation.

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI V. P. SINGH BADNORE) in the Chair]

But Mr. Chidambaram had taken the charge as Finance Minister. He had constituted a single man Committee. Both Houses passed the Finance Bill with the clause, 'retrospective taxation' but the Minister appointed a single man, Parthasarathi Shome. On the recommendation of a single man Committee they over-ruled the decision of this Parliament in the both Houses. I think, Anand Sharmaji remembers that. You mentioned that. Mr. Chidambaram over-ruled...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): There are two speakers. So just adjust, but there is no problem.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : सर, किसी कैबिनेट मिनिस्टर को तो बुलाइए। ...(**व्यवधान**)... अहलुवालिया जी इस बात पर हमारी नाक में दम कर देते थे। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : आप यहां नहीं थे, इस संबंध में बात हो गई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : शुक्ल जी, इस संबंध में सारी बातें हो चुकी हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, my friend has lost two minutes. You have to give him two additional minutes.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I lost two minutes.

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : आपके बाद वालों का भी ध्यान रखना है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI P. RAJEEVE: No; because of this ritual, I lost two minutes.

Sir, UK had already implemented retrospective taxation in 2008 dating back to 1987. If they can, why cannot we? Now, Mr. Jaitley is not ready to implement retrospective taxation. Then, Sir, how can you brand this as tax terrorism. Actually, by quoting this tale, the Government is trying to give more concession to corporate. A corporate bail in this country has, on an average, received ₹ 7 crore every hour or ₹ 168 crores everyday in the form of write off of corporate/income tax! This is the status of revenue foregone in our country. This is in your budget documents. As per this budget document, the provisional write off for corporate is ₹ 5,72,922 crores. This is higher than your fiscal deficit! If you calculate this for the last nine years, it is ₹ 36.5 lakh crores *i.e.*, 36.5 billion rupees.

On gold and other jewellry, the customs duty write off, if you take that 36 months figure, is ₹ 1.67 lakh crores. This is the write off of customs duty on gold, diamond and jewellery.

While replying to my question in this House with regard to revenue foregone, the hon. Minister stated that all these incentives are for creating employment and for boosting economy. Sir, giving all these concessions, corporate share to the GDP has improved only by 5 percentage points in 20 years or 15 per cent.

Sir, after 1991, all Governments have been favouring FDI and corporate. We, the Left, have a consistent position in this regard. At times, we have been mocked by you. Yes; you can ignore our concerns. But what about your own ideologue? Shri Jaitley is not here. But, Nirmalaji would have read two articles written by your own ideologue, Mr. Gurumurthy, in the New Indian Express. Sir, as per Mr. Gurumurthy's analysis -- it is not our ideology; he is your own ideologue -- after giving all these concessions and big

credit from banks, it is more than 47.6 lakh crores! So, FDI and corporate have created just 2.2. million jobs in 20 years since 1991. This is Gurumurthy's analysis. Two decades before 1991, without giving any concessions, private sector corporate added 2.7 million jobs and public sector corporate added 12 million jobs. It was five times of the annual growth rate in the corporate sector in the post-reform period. This is the reality. This is your own analysis. This is Gurumurthy's argument. Sir, on the other hand, Indian corporate constitutes a 5th of the world billionaires with a tally of 70. Sir, there were none in 1991. After explaining all this, Jaitleyji or Nirmalaji, your friend and ideologue, Gurumurthy asked, 'Will the General Budget look beyond corporate sector.' But, Sir, this Budget is intend to protect the interest of the corporate *...(Time-bell rings)...* Sir, I am entrusted to speak for 18 minutes. I lost two minutes. So, I will take 20 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Now, you take two more minutes.

SHRI P. RAJEEVE: Twenty minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Two minutes more.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, 18 minutes for me and rest is for other speaker. As I have already lost two minutes, so I will take 20 minutes. There are 5 minutes more.

Sir, this Budget is proposed to follow FDI in different sectors. Since 1991, all Finance Ministers have been trying to attract FDI. What is the reality? Forty-four per cent of FDI comes from a small country of Mauritius! Only seven per cent comes from the USA and less than ten per cent from Europe. What is the reason behind this? It is the Double Taxation Avoidance Treaty. Are you ready to revisit the Double Taxation Avoidance Treaty with Mauritius, Singapore and other countries? That is my question, Sir. By allowing 49 per cent FDI in Defence sector, foreign companies are getting a controlling stake in the Defence Production Enterprises. It will be detriment to the national sovereignty. Sir, on intensifying inequalities, already our learned colleague also mentioned. The National Sample Survey Report, the monthly per capita consumption of the top 5 per cent is nearly nine times than that of the bottom 5 per cent. This goes up in the urban areas. There, the average consumption by the top 5 per cent of the population was about 14.7 times than that of the bottom 5 per cent. As per the U.N. Report, the top 10 per cent own 53 per cent of the country's wealth while the bottom 10 per cent own only 0.2 per cent of the wealth. This is the reality, Sir. But, we could not find anything to address this issue, to reduce the inequality.

[Shri P. Rajeeve]

Sir, inequality is against the concept of growth. If the income of the majority is squeezed to feed the rich minority, how can they contribute to the growth process? I hope, the Finance Minister and Mrs. Nirmala would have read the recently published classic book, 'Capital in Twenty-First Century' by Thomas Piketty. It is a wonderful book. Piketty is not a Marxist, he is a Keynesian economist. He correctly reveals the inequalities existing in the globalised world and I request the Minister to read that and try to address this issue.

Sir, the total subsidy share in the Union Budget was 17.71 per cent in 2012-13 has declined to 14.5 per cent. We are continuously demanding to revisit the pricing policy of petroleum. As per the CAG Report, the present pricing mechanism benefits Rs.50,513 crores to the oil companies during the five years from 2007 to 2012. I would not like to go into details.

On the agricultural sector, the BJP's manifesto is there; it is for cheaper agricultural inputs, strengthening and expanding rural credit, welfare measures for farmers above 60 years in age; we could find nothing in this Budget Speech. Sir, education and health is the most neglected area in this Budget.

We are strongly opposing the Government's proposal to do disinvestment in the PSUs. The PSUs have a cash reserve of more than Rs.6.5 lakh crores. Also, Sir, the people of India have been struggling because of hike in prices of essential commodities. Education and healthcare expenditure of the people is also drastically increasing, but this Budget has failed to address this issue. They are following the same anti-people policies of the previous UPA Government. This Budget clearly shows that this Government is of the corporates, by the corporates and for the corporates. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P.SINGH BADNORE): Shri A.U. Singh Deo to make his Maiden Speech. How many minutes would you take?

SHRI A.U. SINGH DEO (Odisha): Sir, fifteen minutes only.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P.SINGH BADNORE): Fine.

SHRI A.U. SINGH DEO: Mr. Vice-Chairman, Sir, the present Budget, presented by the respected Finance Minister aims to revive the growth and curb expenditure and borrowing. It points to the right direction. Upholding the fiscal deficit of 4.1 per cent, inherited from the previous Government, the Budget outlines the fiscal deficit in the coming two financial years of 3.6 per cent for 2015-16 and 3 per cent for 2016-17.

Sir, the intent of the Budget is definitely noble. However, what it lacks is a suitable growth orientation. It continues with some of the policies of the past Government. However, it has not brought in adequate structural reforms after the pitiable state of the economy in the recent past. Overall existing Government policies should be replaced with innovative and concise policies. That is what this country requires. Keeping in mind the Hon. Minister's proficiency and competence, I would have expected the Budget to be more focussed, reform active and growth oriented. However, no major structural reforms conducive to the existing situations seem to have been brought in. While it portrays a framework, what it does not reflect is the exact implementation methods for the same. While I believe it is an ambitious effort, I would think it to be a baby-step towards the much-needed larger goal of fiscal consolidation. But, Sir, Rome was not built in a day, and we must give our competent Finance Minister more time.

Sir, under the current Budget, to obtain the fiscal deficit of 4.1 per cent, three things are of utmost importance; to curb, maintain or even reduce inflation rate in the country; to ensure the expected expenditure does not exceed the estimate; and the revenue is as per the estimate. Further, a lot of reliance is here on the Government's ability to collect taxes, ensuring timely and honest payment by taxpayers, and correct the tax evasion scams that have been happening in the past. It is a daunting task. सर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा और वह यह है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के एस्टीमेट्स को एक्चुअल्स के साथ कम्पेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि हमारे सामने क्या समस्या आ सकती है? The tax revenue collected was 5.22 per cent lesser than the Budget Estimate. That means, Rs.34,629 crores. In borrowings, there was a substantial increase of 25 per cent as compared to Budget Estimate. The difference is, Rs.1,03,173 crores. The expenditure increased by 3.71 per cent. Sir, as this happened, the fiscal deficit in the year increased to 5.7 per cent, significantly higher than the estimated Budget of 4.6 per cent as shown in the Budget. तो यह गुस्ताखी इस बजट में न हो, इसका मंत्री जी ध्यान रखें।

सर, मेरी एक और कंसर्न है और वह यह है कि हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम होती चली जा रही है। यह हमारे रिसोर्सेज के लिए ड्रेन है। हम विदेश से काफी मात्रा में ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। इसीलिए हर दिन पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीजों के दाम बढ़ते हैं। अगर पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़े तो मार्केट में हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। हमें इसे कंट्रोल करने की जरूरत है और अगर हम अपने बजट का इम्प्लीमेंटेशन ठीक रखेंगे, तो यह कार्य हो सकता है।

सर, वित्त मंत्री जी ने 29 स्कीम्स में हरेक स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। यह बहुत लिबरल एलोकेशन है और हम इसका सम्मान करते हैं। While this is commendable,

[Shri A.U. Singh Deo]

one of the biggest problems glaring the country in the face of reality is that of women safety. Crimes against women are highly on the rise. The reporting of incidences of rape, not to mention other offences of immoral trafficking, incestuous acts, dowry deaths, have increased by 35 per cent in the last one year. However, the Finance Minister, in his Budget, has made a meagre allocation of Rs.150 crores to a scheme to increase the safety of women in larger cities. As I understand, the word 'larger cities' has been used. While I understand the Finance Minister's stance of various allocations being made on pilot basis, considering the vast population of women in the country, I would like to ask, क्या वीमेन सेफ्टी के लिए ये 150 करोड़ काफी हैं? Is the safety of women negotiable?

सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू के लिए, जिन्हें हम सब सम्मान देते हैं, गुजरात में 200 करोड़ दिए गए हैं। उससे भी कम वीमेन सेफ्टी के लिए दिए गए हैं और वह भी सिर्फ लार्जर सिटीज के लिए दिए गए हैं। क्या छोटी सिटीज में लेडीज नहीं होती हैं? उन्हें क्या छोड़ दिया गया है? जो गंभीर समस्याएं लार्जर सिटीज में होती हैं, वे छोटी सिटीज में भी होती हैं। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि छोटी सिटीज को क्यों छोड़ दिया गया है? इसका क्या रेशनल है? वह बताएं। The ruling manifesto speaks of important schemes for education, health and drinking water. इलेक्शन कैम्पेन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी प्रोमिसेस की थीं कि हम provision for sanitation facilities for women करेंगे, हर घर में बाथरूम होंगे, हर स्कूल में बाथरूम होंगे, लेकिन यह चीज पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए फाइनेन्स मंत्री जी द्वारा एक इनीशियल टोकन बजट दिया गया है। 'निर्मल भारत अभियान', एक रूरल सेनिटेशन स्कीम है, उसमें पूरे भारत के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए 4,260 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि यह पैसा बहुत कम है, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार चाहती है कि पूरे देश में 2019 तक सेनिटेशन का काम कर सकें, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इतनी देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे पहले करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान are they inclusive of the drinking water and sanitation facilities that the P.M. has promised? Will there be a redressal mechanism in place for those aggrieved for lack of these facilities With the history of corruption and instances of money flowing into the pockets of undeserving and dishonest, I hope the Government will have an airtight mechanism to check financial allocations.

The Central Government in its Budget allots funds to the States under various schemes to be released to the States in a timely, adequate and responsible manner. During recent years, however, the Central Government has been resorting to sizable plan cuts which adversely impacts the health of States and implementation of the schemes. So, under the Accelerated Irrigation Benefit Programme, the State of Odisha, for instance, received only ₹ 38 crores as against its actual expenditure of ₹ 1084 crores. इतना काटा, सर। For 2012-13 again the State received only ₹ 15 crores during 2013-14 as against its

actual expenditure of ₹ 967 crores. Under MNREGA too the State received only ₹ 757 crores against the Central approved share of Rs.1363 crores during 2013-14. Thus, the State's fiscal condition and implementation of the on-going socio-economic development programme get adversely affected.

महोदय, मैं एक बात के लिए फाइनेन्स मंत्री जी की तारीफ करुंगा कि आप रिवीजन ऑफ मिनरल रायल्टी पर आ गए। ये जो स्टेट्स हैं ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये relatively rich in mineral wealth हैं। बहुत दिनों से हम मांग कर रहे हैं कि हमारा यह रिवीजन ऑफ मिनरल रॉयल्टी हो। आप जानकर हैरान होंगे कि अगस्त 2012 से ओडिशा से पांच करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है, क्योंकि मिनरल रॉयल्टी इन्क्रीज नहीं की गई। इसे इन्क्रीज करना बड़ा जरूरी है। हम फाइनेन्स मंत्री जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देंगे कि वे इसे सामने ले आए हैं। एक और चीज है कि ओडिशा में कुछ बड़े लोग हैं, माइनर्स हैं, जिनके पास हजारों माइन्स हैं। They control many mines in the State of Odisha. तो हमारी राज्य सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बहुत दिनों से यह मांग रही है कि हमें परमिशन दी जाय, या सेन्ट्रल गवर्नमेंट चार्ज करे, एक मिनरल रिसोर्स रेंट टैक्स हो। जिनकी इन्कम हजारों करोड़ में है, जो एक लेवल के ऊपर हैं, उनके ऊपर एक स्पेशल टैक्स लगाने की मांग ओडिशा सरकार बहुत दिनों से कर रही है। इसके लिए हमारे फाइनेन्स मंत्री जी से गुजारिश है कि वे इस पर ध्यान दें। It is not Odisha specific. It may be also required in Jharkhand and Chhattisgarh. You might inquire into the matter and make a principle rule on the issue.

सर, एक चीज है कि इस पक्ष के भी किसी बन्धु ने बात करते हुए कहां था कि 'नवकलेवर फेस्टिवल' ओडिशा में 2015 में मनाया जाएगा, जिसमें कम से कम fifty lakh people come and visit Orissa in this month. The Government of Orissa has requested for Rs. 1,397 crores to augment this festival. We request the Finance Minister to look into the matter because the request is being made since May 2013. थोड़ा उसको देखें। यह हमारे देश की एक शान है। यहां बहुत विदेशी आते हैं। टूरिज्म की दृष्टि से यहां तीस-चालीस लाख लोग आते हैं और उनको वहां रखना मुश्किल होता है।

सर, एक और चीज हम ओडिशा के लिए मांगते आ रहे हैं और वह है एक 'स्पेशल कैटेगरी स्टेट'। हम लोग गरीब हैं और वहां काफी लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, इसलिए 'स्पेशल कैटेगरी स्टेज' हमें मिलना चाहिए। उसका सिर्फ एक ही आंकड़ा हमारे साथ नहीं है, जो उसको क्वालिफाई करे कि हमारे स्टेट की बाउंडरी से किसी दूसरे देश की बाउंडरी नहीं लगी है। एक ही चीज माइनस है, जिसकी वजह से यह हमें नहीं मिला है। I hope the hon. Minister and the Government will consider that States like Bihar and Orissa get this benefit of a 'Special Category State'.

Now, I come to introduction of Goods and Service Tax (GST), which replaces all existing indirect taxes on goods and services with one single tax, thus lowering the tax

[Shri A.U. Singh Deo]

burden. The decision of the Government to introduce and implement the GST will unify 29 States of India into a common market to boost revenue; and, at the same time, it will make easier to do business. However, the Budget fails to lay down a clear roadmap for implementation of the GST, which would have been a welcome gesture. The Union Government had assured to compensate the State Governments for loss of revenue due to reduction of Central Sales Tax, until the implementation of GST. Accordingly, the GST was reduced from 4 per cent to 3 per cent and from 3 per cent to 2 per cent in 2007 and 2008 respectively. The State of Odisha however received only ₹ 256 crores towards compensation, against the loss assessment of ₹ 644 crores. तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, इनको सुधारने की जरूरत है।

सर, रेलवे का बजट पास हो चुका है and I would just touch on the subject.

रेलवेज़ में प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए और एक्सपेंसेज कम करने चाहिए। However, the Government seems to have taken an easy way out by increasing rates, without any serious attempt to reduce costs by removing inefficiencies in the system. सर, हमारी इंडियन रेलवेज़ का 6 परसेंट प्रॉफिट है, जबकि कनाडा का 40 परसेंट प्रॉफिट है। ...(**समय की घंटी**)... तो हम केवल टिकटों और दूसरी चीजों को बढ़ाने की न सोचें, कॉस्ट रिडक्शन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, जो हम देते नहीं हैं। The Finance Minister has expressed his helplessness over his inability to substantially cut tax rates or increase allocation to much-needed social sectors because of lack of availability of resources.

सर, मैं डिफेंस का एक एक्जाम्पल देना चाहूंगा। उनके डिफेंस डिपार्टमेंट में, under the garb of life-cycle cost method, the Ministry of Defence has bought air defence platforms at almost 40-50 per cent higher prices than the lowest off-the-shelf bidder. This is because none of the other costs associated with LCC -- such as, supply of spare parts, fuel efficiency, technological amalgamation -- are contractually binding in nature, thereby creating an excess expenditure of thousands of crores.

सर, अब मैं आता हूं ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : आप दो मिनट और ले लीजिए। आपने पन्द्रह मिनट मांगे थे, तो पन्द्रह मिनट हो गए हैं। आप दो मिनट और ले लीजिए।

श्री ए.यू. सिंह दिव : सर, मैं पांच मिनट और लूंगा। There is a proposal to increase in the FDI from 26 per cent to 49 per cent in Defence and Insurance sectors.

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : इनकी यह मेडन स्पीच भी है।

श्री ए.यू. सिंह दिव : सर, कौन 49 परसेंट लगाएगा? बाहर से आकर कौन हिन्दुस्तान में 49 परसेंट लगाएगा और कंट्रोल दे देगा इंडियन गवर्नमेंट को? यह होता नहीं है, यह हो नहीं सकता।

अगर कोई आकर इन्वेस्ट करेगा, तो 49 परसेंट लगाने के लिए उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा। तभी वह आएगा। अभी जो कम्पनियां हैं, जो इंडिया में बेचती हैं, डिफेंस में, they are 100 per cent owned by foreign investors. They come into India, they sell in India and they make 100 per cent profit. So, why should he come and give you 49 per cent when he owns a company 100 per cent and making a profit of 100 per cent? यह सोचने वाली बात है।

हम देख रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट होता है, वह कांस्टीट्यूएंसी स्पेसेफिक हो जाता है। जो सरकार आती है, वह अंडर प्रेशर हो जाती है, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, एम.एल.ए. से, और उस तरफ का डेवलपमेंट हो जाता है। आज बी.जे.पी. की सरकार है, कल यू.पी.ए. की सरकार थी, ये लोग अपनी तरफ का डेवलपमेंट करने लग जाते हैं। मैं फाइनेंस मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि there should be promotion of an equitable society and an equitable development of the county. सर, एक एरिया है, कालाहांड़ी, बालांगीर, कोरापुट–के.बी.के. एरिया – वह सबसे गरीब एरिया है। हम दस साल से अधिक समय से सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब हम बी.जे.पी. सरकार से मांग रहे हैं कि हमें पांच साल में दस हजार करोड़ रुपए दिए जाएं। It is the most poorest region in the county. There is no doubt in it. I invite the hon. Minister to come and have a look at that place. एक खुर्दा रोड-बालांगीर रेल लाइन है, जो कभी खत्म होने में नहीं आती, वह 17 साल से चल रही है। उसके लिए भी रिक्वेस्ट की गयी है। लेकिन इस साल हमें मात्र सौ करोड़ रुपए दिए गए है। सर, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, please bear with me.

सर, अब मैं मेडिकल कॉलेजिज़ के बारे में कहना चाहता हूं। The last UPA Government announced 59 new medical colleges in the country. 3 new colleges in Odisha received approval earlier three year. What has happened to them? On the gound, there is no work. No medical college has been started. क्या है, कितना पैसा है, कब देंगे, कब शुरू करेंगे, या यू.पी.ए. सरकार गयी और वह स्कीम भी गयी, वह मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर, आप आई.आई.एम. दे रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज दे रहे हैं, आई.आई.टीज दे रहे हैं- फाइनेंस मंत्री यह सब दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी जो कॉलेजिज हैं, स्कूल्स हैं, जिनमें पढ़ाई नहीं होती, जिनमें मास्टर नहीं हैं, जहां बच्चे टूटे हुए कमरों में बैठे रहते हैं, उनके लिए यह सरकार क्या कर रही है? आप नयी चीजें दे रहे हैं, we are very happy that they are giving us new institutes. But, what about the absolutely rocky mechanism of running schools in this county today? Sir, I am finishing now.

Sir, now I come to retrospective taxation.

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर) : ओडिशा के बारे में कुछ दूसरे स्पीकर्स के लिए भी छोड़ दीजिए।

श्री ए.यू. सिंह दिव : यह सबसे गलत चीज है। It is a disincentive for getting foreign investment. आज बी.जे.पी. सरकार है, वह ले आती है, कल सरकार चेंज होगी, यू.पी.ए.

[Shri A.U. Singh Deo]

सरकार आ जाएगी, they will look at it in a different manner. This can be misused. I don't think this provision should be there at all in the country. Sir, I am concluding now. मैं पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे भाई अभी बोल रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था। आप जितने खाद्य पदार्थ पैदा कर लीजिए, जितनी इंडस्ट्री बढ़ा लीजिए, it will never be enough. Indonesia, which is the biggest Muslim country, has established population control. Why can't we do it? This is something which needs to be looked into by the Government. It is very easy. The formula lies there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Thank you very much.

SHRI A.U. SINGH DEO: Sir, I am concluding now. To conclude, Sir, I would say that the Budget includes measures to support faster economic growth. It would be unfair to say that it is an unsatisfactory Budget. However, we would have liked to see more than just intent on several areas such as GST, DTC, retrospective taxation, details for achieving the fiscal deficit targets, etc. There are many progressive and far-sighted policies and changes in the new Budget, which I believe, if implemented properly, will be an economic changer. I know that the Hon. Finance Minister is proficient and competent to set right the economy of the country. I wish him the best of luck.

SHRI H.K. DUA (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is an interesting debate that has been going on for hours and it will continue tomorrow. I will pick up an aspect which has not been touched so far. A chunk of the Budget relates to Defence. Sir, it is an interesting situation in the country that the Defence Minister is also the Finance Minister. It can be used very creatively. But I find from the Budget and the allocations for Defence that while the Defence Minister has been demanding greater allocation, Finance Minister, Arun Jaitley, himself has been cutting into that demand and reducing the expenditure. I don't know on how many projects and how many schemes he has been conservative and become more pragmatic. I thought as a Defence Minister, Arun Jaitley should be more demanding, and, as a Finance Minister, he should be less restrictive. But, he must be having some compulsions.

The Defence expenditure should be related to two specific factors -- one is the present threat to the country's security and the second is, what is the likely scenario over the next few years and how far we are prepared to meet the future threats. Unfortunately, no Government, in the past or till now, has really spelt out its own assessment of threat perception to the Defence forces – leave aside to the country -- that this is the threat perception over a period of time and this is what we are going to do. That will help the Defence forces, if they do it. Even now it is not too late; and it helps the country to prepare in advance, allocate resources, make plans and make preparations.

The security situation at present is not congenial for us, we continue to face two front situation -- in the West from Pakistan and China from the North. Both are nuclear powers and both are not well disposed to us as it is often comes out in public statements. Along with these, there is threat from terrorism. That is an additional threat. The country would like to be assured that this kind of Defence Budget ensures the kind of security required in this kind of environment.

Sir, the increase in the Defence Budget is 12.4 per cent. It is hardly an increase. It is almost peanuts. A chunk of it goes to increase in the salaries and pensions; and a very limited amount is left for fresh expenditure. A altr Rupees five thousand crores have been provided for modernization, badly needed by the three Services. We are not having the kind of technology which a country like India should be having, with its ambitions to become a major power of 21st century -- political, economic, military and even nuclear. This ₹ 5,000 crore for modernization is a very limited amount which the Finance Minister has provided for. This needs to be relooked even under the present economic circumstances.

Sir, particularly, we need to attend to the needs of Air Force and Navy. I will particularly emphasize the Navy, considering how China is venturing into the Indian Ocean and developing its Navy, Blue Water Navy, to reach right up to African coast. They have got a base south of Burma; they have facilities in Sri Lanka, and in the Indian Ocean they are reaching otherwise also to Gwadar, which port they have developed for Pakistan – basically for themselves – and they are also trying to avail facilities in Seychelles and Eastern Coast of Africa. The threat to India's coast can be come considerable over a period of time. So, we have to spend more on the Navy. We have a new aircraft carrier which was welcome and much more needs to be done to make it a more effective Force. Sir, in the last two years, the Navy has suffered as many as 17 accidents.

And, some of our ships, particularly submarines, have got damaged; our effective submarine strength has got depleted in a way. That needs to be strengthened rather speedily, because otherwise, it would be a dented Navy trying to meet developing threat. Of the enquiries which have been conducted into the naval accidents, only four or five have come to some conclusions; all others are still going on. I want to know, why these inquires, in a vital area should take that long. I think, the Government needs to look into why Navy should take that long to finish its inquiries and take necessary steps.

Sir, there are many plans which have not yet been implemented. We did provide for another strike corps for the Eastern sector to meet the Chinese threat. There is a need for a second strike corps for the Western Sector. I don't think Parliament will grudge

[Shri H.K. Dua]

sanctioning extra money for doing that kind of an exercise urgently because it takes about five years to develop a strike corps.

Sir, the Naresh Chandra Committee Report, recently, is said to have recommended three new commands to meet new kinds of threats. One is, aerospace command; another is, cyber command. We face considerable threat from the Chinese, and it can be some others also, who could launch a cyber attack on our facilities, which can be dangerous and which can immobilize our capabilities. The third command in the Naresh Chandra Committee Report, which has not yet been made public but which everybody knows as it is fairly open, was that there should be a special command to counter terrorism. What it should do, how it should do, that we don't know, but there should be a separate command to counter terrorist threat coming from outside, which, for us, is a major challenge.

Sir, there is another proposal in the drawer. Over the years, no decision has been taken and it calls for it, one way or the other. The Kargil Review Committee had recommended a Chief of Defence Staff, who could integrate the working of all the commands under him. Now, that kind of a proposal is urgent. Most countries have gone in for a Chief of Defence Staff. We, with the large Army, a fairly large Air Force and a fairly large Navy, which is yet to be modernized in many ways, need a Chief of Defence Staff who could integrate these forces. Who it should be -- whether it should be, at times, the Army, the Air Force or the Navy -- all those kinds of things could be worked out but there should be that kind of a set up where integrated, coordinated decisions are taken without delay. Of course, it has to remain accountable. *(Time-bell rings)* I will just take a couple of minutes. Sir, I am conscious of the time factor.

Sir, the Budget provides for ₹ 1000 crore for one rank-one pension. It goes some way to meet the demand of ex-service personnel, but not all the way. I think, it is better to be through with that problem, which has been hanging fire for a long time, as it affects a large number of people who have retired and who think they have been discriminated against in getting the pensions. What else do we need to do? It is a long list, but I won't take that much time. Maybe the Committees could take time and maybe we could talk about it when a regular debate on Defence is held, which is unlikely during the next couple of Sessions but I don't find this Session providing for a debate on the Ministry of Defence. This allocation that is there needs to be relooked and possibly, some rearrangement can be made in the figures.

Luckily, this Budget is possibly valid for the next eight months. Maybe, the Defence Minister or the Finance Minister is working out on an eight months' time scale. But, in

the November Winter Session of Parliament, if they come with Budget, they should take care of the kind of threat, the kind of expenses we ought to incur and we are not able to incur by November Budget, in case there is one. And I plead this should be relooked into and let there be a supplementary Budget in the Winter Session of Parliament. I am sure, Parliament will not deny the Defence Minister or the Finance Minister the funds required. Thank you.

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, I rise to support the Motion and compliment the hon. Finance Minister for presenting a balanced yet progressive Budget under such adverse conditions. Please consider the legacy that he inherited, an economy which had totally lost steam, a manufacturing sector which was showing a negative growth rate, double digit food inflation, progressively high unemployment, tax terrorism, crony capitalism, misuse of agencies like CBI and IB for political sustenance and the feeling of despondency all around. Hence, it was not surprising that the people of India gave an absolute majority to the BJP and NDA after thirty long years. Under these difficult circumstances, within forty days of assuming office, Mr. Jaitley with this Budget has pulled a rabbit out of the hat and deserves the nation's applause. So, what impresses me most about this Budget is a fact that he has increased the Plan Outlay by 26.9 per cent and, at the same time, announced an Expenditure Commission to suggest ways and means of cutting the Government's flab which was long overdue. Sir, these steps would go a long way in pushing up the growth rate and controlling our fiscal deficit in the future. Sir, the previous Finance Minister in order to show a healthy fiscal deficit resorted to window dressing in a big way. He postponed subsidy expenses to the next financial year, stopped payment of duty drawbacks to the exporters, income tax refunds were also stopped for many months and he preponed income by making PSUs declare 5 to 600 per cent dividends thereby severely impacting their health and future growth. Nationalised banks were forced to lend lakhs of crores to some of the favoured cronies and all these loans have now turned to NPAs seriously impairing the health of the entire financial system. All this left very little headroom.for Mr. Jaitley to manoeuvre without causing an alarm in the financial markets. Sir, Mr. Jaitley has wisely decided to recapitalize the nationalized banks in order to bring them at par with Basel-Ill norms. He has announced that their equity will go up by ₹ 2.40 lakh crores in stages. He has further emphasized that the equity would be infused by retail investors while, at the same time, the Government will keep control. The hon. Finance Minister has made the PSUs role in growth very explicit by proposing that they would invest ₹ 2.47 lakh crores in order to create a virtuous investment cycle. Mr. Jaitley has allocated an amount of ₹ 37,800 crores for building highways and State roads so as to

[Shri Naresh Gujral]

initiate development of expressways in parallel to development of industrial corridors. Rupees five thousand crores have been allocated for warehousing to strengthen the infrastructure for scientific storage of foodgrains and perishables. In addition, an amount of ₹ 2,000 crores has been earmarked for food processing. Sir, this would certainly help contain normal rise in prices of fruits and vegetables during non-produce season. After many years, attention has been given to the agriculture sector. The Finance Minister plans to finance five lakh landless farmers through NABARD. Adequate institutional finance has been provided for both long- term and short-term needs of our farmers through NABARD. In order to ensure that our farmers do not have to run to moneylenders, he also made provision for their immediate needs. Irrigation too has received the Finance Minister's attention as two-thirds of our agriculture is still rainfed. He has proposed an initial sum of ₹1,000 crores for creating the infrastructure for rural irrigation schemes.

Sir, he has set aside ₹ 10,000 crore for startups in the SME sector. Excise duties have been reduced to give impetus to manufacturing sector, apart from allowing manufacturing units to sell their products through e-commerce platforms. For greater participation of the SMEs, the investment allowance threshold is proposed to be reduced from 100 crores to 25 crores.

In a major boost to urban development, the budgetary allocation has been raised by 133 per cent from approximately ₹ 7,500 crores to over ₹ 17,600 crores. This includes more than ₹ 7,000 crore for 100 new smart cities.

Sir, of late, our savings rate has been stagnant. By increasing the income tax exemptions, he is making sure that the man on the street not only has more money in his pocket to spend but also has the incentive to save. It is savings that convert to investment. Yet, our domestic savings rate is not high enough to meet our investment requirements. So, wisely, the hon. Finance Minister has made it easy for the FDIs to step up their investments in India.

Threshold limits have been raised to 49 per cent in Defence and Insurance sector, and, 100 per cent in e-commerce. Sir, you would recall that till 2009, India was a favourite destination for many global giants that were looking for an alternative to China. They wanted to set up manufacturing plants as well as back offices in India. However, the announcement of retrospective taxation, GAAR, and the transfer pricing hassles startled the multinationals and they started applying brakes on investments here. The hon. Finance Minister sent a soothing message to the international community that they would have

ease of doing business in India, and, they would not be subjected to tax terrorism in future.

Sir, India is one of the largest importers of defence equipments. For years, we have been happy to import bulk of our requirements but have refused foreign companies a chance to set up manufacturing as well as assembly plants in India. Sir, personally, I wish that this limit had been raised to 51 per cent because only then serious transfer of technology would take place. However, the Finance Minister, who is also the Defence Minister, has perhaps decided to tread cautiously into this uncharted territory. By strengthening and empowering the Income Tax Settlement Commission, the hon. Finance Minister is giving a chance to our businessmen to come clean, and, the Government can mop up the much required revenue from approximately 4.91 lakh crore stuck up in disputes.

The Kisan Vikas Patras will help channelize money to the economy, which so far was going for the accumulation of gold, thereby severely impacting our Current Account Deficit (CAD). The disinvestment target of ₹ 57,000 crore would certainly help in reducing the Government's borrowings, which, in turn, would ease pressure on our banks to lower interest rates and create room for the private sector to borrow at sensible rates of interest. Sir, India is a unique and diverse country with history dotting every nook and corner of our land. Yet our tourist arrivals are only one-tenth of that of China. Tourism can potentially be a huge foreign exchange earner as well as a massive employment generator. The hon. Finance Minister has wisely laid emphasis on this much-neglected sector by providing Rs. 900 crores for tourism promotion, apart from easing the visa regime.

Sir, all this means that Mr. Jaitley has taken care of both the demand as well as the supply side in order to kick start the economy, which I am sure will lead to an accelerated growth rate, job creation and tackling the persistent high inflation.

The hon. Minister has re-emphasised his commitment to the early introduction of GST which can be an absolute game changer for our GDP. I hope that he will be able to bring all the States on board very quickly and address their concerns and fears.

Sir, he has also promised to examine in detail the Direct Tax Code which is long overdue. ...*(Time-bell rings)*... I would implore the Finance Minister to announce in his reply to this debate that it will certainly see the light of the day when he presents his next Budget in February, 2015.

Sir, I am now turning to my State of Punjab which is the granary of India and has given strength to India by making the country self-reliant in food. In this process, our

[Shri Naresh Gujral]

State has completely depleted our water reserves. Even in years of drought, you would recall, Punjab continued to feed the nation. Sir, I would implore the hon. Finance Minister that our canals need to be repaired, our canals need to be renovated. So, kindly, in one go, sanction enough money so that we can take care of our canals.

Also, in the Presidential Address, the Government had said that the FCI would be reorganised. Sir, we have claims of Rs. 10,000 crores against the FCI which are long overdue. I would implore the Finance Minister to please appoint an arbitrator so that these claims can be fixed expeditiously.

Sir, you would also recall that the UPA Government had said that the debt of Punjab, West Bengal and Kerala would be restructured. So far nothing has been mentioned in the hon. Finance Minister's speech in this regard. I do hope that he will take care of this in his reply to the debate. *(Time-bell)*

Sir, the BJP is giving me ten minutes from their time.

श्री अविनाश राय खन्ना : सर, हमारी पार्टी का कुछ समय इनको दिया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Okay. Please, carry on.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, the welfare of the farmer is pivotal for our country as two-third of India still lives on agriculture. We have to ensure that our farmer earns a decent living. He has been increasingly finding it difficult to cope with the inflation. Sir, the farmer of this country must get a fair price for his produce.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

I would say to the Finance Minister that we were all a little disappointed when the MSP was announced. MSP must be in line with the inflation rate of the country. *(Time-bell)*

Sir, they have given me ten minutes from their time.

श्री वी.पी. सिंह बदनौर : सर, बी.जे.पी. ने उनको अपने पांच मिनट दिए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Then, there is no problem.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, I do hope that the Government will reconsider the announcement on MSP.

Sir, the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, has unveiled a new economic vision for India. As a result, once again, there is a hope and expectation, especially

amongst our youth. They are expecting good times to come back and the nation to see a double-digit growth rate. This is no easy task unless the Government fearlessly ushers in some structural changes which are long overdue. Sir, for the hon. Finance Minister's consideration, I have four suggestions to make. Urgently make changes in the Land Acquisition Act. I had warned earlier also, when this law was being debated in this House, that while the new Act must be farmer-friendly, it should not be anti-industry, which unfortunately it is. Without easy availability of land at fair market prices, we cannot expect to achieve our growth rate targets as well as provide jobs to our millions of youth.

Two, boldly introduce labour reforms. Again, it does not mean that policies have to be anti-labour. China, despite being a communist country, has made its labour accountable. And since we are determined to make India a manufacturing powerhouse, it is imperative that we also introduce changes in our antiquated labour and factory laws.

Three, we must invest heavily and urgently in the judicial infrastructure if we wish to eliminate corruption as well as maintain sanity in our society. We cannot afford to have lakhs of cases pending in courts for decades as this is leading to criminalisation of our society at every level.

Lastly, we must create an environment where our wealth creators are respected and not looked down on. They are the ones who create millions of jobs that are so desperately required.

Your ₹ 10,000 crore fund for start-ups will create lakhs of jobs and hopefully a new generation of successful entrepreneurs and business leaders. This country must learn to celebrate them.

Sir, the need of the hour is to think in an unconventional manner and welcome change. I end by quoting the great poet Iqbal. For those of my friends who are not familiar with Urdu, it means, "To be afraid of new ideas and to be stuck in old ways, is what creates difficulties in the lives of nations." I quote:

'आइने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना,
मंजिल यही कठिन है, कौमों की जिन्दगी में।'

Thank you, Sir.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI (Rajasthan): Hon. Deputy Chairman, Sir, let me begin by congratulating the Leader of the House on holding two of the most important

[Dr. Abhishek Manu Singhvi]

portfolios of any Government, indeed on being India's first Finance Minister and Defence Minister on a regular basis.

When you have the talent, the temperament, the intelligence and the coherence of Mr. Jaitley, you suffer from one disadvantage. Because it is natural to expect a lot. And if you add the hype and hoopla accompanying Mr. Modi's campaign to these qualities, then I think there is a large legitimate expectation that you will have something with innovative novelty, with radical restructuring reform either a big bang or at least a reasonably medium vision, a new direction and a new philosophy.

Hon. Members, sadly, each of these is lacking. It is sad because the Finance Minster himself rightly notices in the first sentence of possibly the longest ever Budget speech that there is a verdict for change. And it is a massive mandate. But sadly it has largely been frittered away. In fact, knowing his ability, I am not sure whether he would own authorship and ownership of all parts of the Budget speech, because it appears that the labyrinth of bureaucracy and bureaucrats has taken over somewhere in the minutiae and the details of the Budget speech.

Let me, therefore, begin by noticing that in the last fifty days, whatever else we have seen or not seen, one thing is clear that there is this constant lamentation that this Government has inherited something horrible, something so poor and that this is something so rotten in the State of Denmark that this Government cannot handle the heritage, the lineage and the legacy which it has got. I find that to be curiously continuing right through the first fifty days. So, I will also start with the legacy which we left. I will then deal with not insubstantial components of double speak and hypocrisy which is there. Thirdly, a very brief comment on what you have learnt about how imitation is very flattering. But we are not swollen by flattery. Then come to some specific criticisms of the Budget. Their talk on legacy is very amusing and Shakespeare said, "No legacy is so rich as honesty." I only wish that the NDA with this massive mandate had practised a little more honesty when they talk of legacy they have inherited. हमने क्या विरासत, क्या पूंजी दी है? यहां पर मेरे पास 10-12 कसौटियां हैं और आश्चर्य की बात यह है कि हर कसौटी में - मैं अभी आपको कुछ संक्षेप में बताऊंगा-यू.पी.ए. वन की परफॉर्मेंस एन.डी.ए. से कहीं ज्यादा है और यू.पी.ए. टू की परफॉर्मेंस भी एन.डी.ए. से कहीं ज्यादा है, यद्यपि यू.पी.ए. टू की परफॉर्मेंस यू.पी.ए. वन के पीछे है। अगर हम इसे तुलनात्मक रूप से देखें और जो एवं ठोस आंकड़े हैं, वे हैं छः वर्ष एन.डी.ए., पांच वर्ष यू.पी.ए. वन और चार वर्ष यू.पी.ए. टू, क्योंकि यू.पी.ए. टू के आखिरी वर्ष के पूरे आँकड़े नहीं दिए गए हैं, यद्यपि मेरे पास हैं और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। यदि हम इन छः, पांच और चार की तुलना करें तो आप

पाएंगे कि अगर सही स्पर्धा है, सही कॉम्पिटीशन है, तो वह यू.पी.ए. टू. और यू.पी.ए. वन के बीच में हैं, क्योंकि इन कसौटियों, इन आंकड़ों के आधार पर यू.पी.ए. टू ने यू.पी.ए. वन जितना अच्छा नहीं किया, लेकिन दोनों ने एन.डी.ए. से कही बेहतर किया है। मैं इसमें राजनीति या रिटॉरिक नहीं ला रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर मैं इसे संक्षेप में आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

आप कई कसौटियां ले लें। जी.डी.पी. ग्रोथ ऐनुअल-ऐवरेज, आप सेक्टर्स को डिवाइड कर ले तो उसमें है-कृषि की ग्रोथ, औद्योगिक ग्रोथ, सर्विसेज सेक्टर का विकास, गरीबी रेखा से कितने लोगों को ऊपर उठाया गया, फिस्कल डेफिसिट, औसतन सेविंग्स का रेट, इनवेस्टमेंट का रेट, बिजली उत्पादन का रेल, बिजली के विषय में जेनेरेटेड कपैसिटी जोड़ने का रेट, सीमेंट प्रोडक्शन, फूडग्रेंस, इत्यादि। ये लगभग 15 कसौटियां हैं और मैं इन्हें किसी के भी साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं। आप किसी भी कसौटी को ले लें, तो यू.पी.ए. वन के आंकड़े औसतन प्रति वर्ष एन.डी.ए. से कहीं ऊपर, यू.पी.ए. टू के भी आगे और यू.पी.ए. टू. के यू.पी.ए. वन से थोड़े पीछे हैं। यह स्पर्धा किसकी है? यह आपको कैसी विरासत मिली? हमने आपको यह कैसी पूंजी दी? क्यों इतना कहा जा रहा है कि आपको विरासत में करीब-करीब एक बैंकरप्ट देश मिला?

अगर आप जी.डी.पी. ग्रोथ को लें तो यह 9 प्रतिशत और 8 प्रतिशत है तथा औसतन आपकी सबसे ज्यादा, हमारी लोएस्ट औसतन रेट से ऊपर है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ आपका तीन से कम है और हमारा साढ़े तीन तथा आखिरी वर्ष में साढ़े चार था। औद्योगिक विकास यू.पी.ए. वन में प्रति वर्ष औसतन 9 प्रतिशत पहुंच गया था और यू.पी.ए. टू में यह 6 प्रतिशत पर था, यानी दोनों एन.डी.ए. से आगे थे। गरीबी रेखा में कुछ अद्भूत फिंगर्स हैं। इसे हम रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में 41 परसेंट से 25 परसेंट के आंकड़े पर ले आए, यानी इसे हमने 16 प्रतिशत कम किया और अर्बन में हम इसे 25 परसेंट से 13 परसेंट पर ले आए। अगर दोनों को मिलाएं तो औसत 37 परसेट से घटकर 21 परसेंट पर आ गया था।

इस प्रकार के बहुत आंकड़े हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आप करें, आपके पास मैनडेट है। आप जो अच्छा करें, वह देश के लिए अच्छा होगा, हम भी जहां तक होगा समर्थन करेंगे, लेकिन कम से कम बार-बार यह विलाप न करें, जो कि 50 दिनों में कई बाद किया है कि आपको विरासत में एक बैंकरप्ट और करीब-करीब एक खत्म नेशन मिला। इसके अलावा, इसमें अन्य कई आंकड़े हैं, कई कसौटियां हैं। हम करेंट अकाउंट डेफिसिट को 1.7 प्रतिशत पर ले आए, फॉरेन एक्सचेंज रिंजव्स 300 प्रतिशत बढ़े, पूर्व कॉमर्स मंत्री यहां हैं, यू.पी.ए. के समय में एक्सपोर्ट 646 परसेंट रहा। मोबाइल्स एक्सपेंशन from 13 per cent, mobile penetration in India, यानी किन-किन कोनों में मिलता है मोबाइल। 13 प्रतिशत था 2004 तक। हमारे वक्त में जब अंत हुआ तो 72 प्रतिशत and I am happy to note that the Telecom Minister is also here. I end on this first point of legacy by pointing out...

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : 72 परसेंट ग्रामीण में बताया आपने?

डा. अभिषेक मनु सिंघवी : नहीं, नहीं, all India mobile penetration, from 2004 till today, has risen from 13 per cent to 72 per cent. Your Department has the figures much more easily than I have. I have to search for them. So, hon. Members, don't make the cardinal mistake assuming that because you have won the elections, everything which we have done is wrong. Winning elections is fifty-fifty per cent game. You win some, you lose some, but do not assume that a loss on our side or a win on your side validates either any of your performances or, in fact, invalidates what we have achieved.

The second point briefly is, some amount of hypocrisy, hype and double-speak or double standards going along. There are several examples and we are happy. You have been told about FDI insurance. The former Finance Minister, in fact, called upon the then Leader of the Opposition in each of the Lower and Upper Houses, had parleys, persisted and yet the 49 per cent figure was opposed tooth and nail when you were sitting this side. Example number two was even more egregious. The GST, which finds a pride of place in the hon. Finance Minister's Budget, you started it in 2000. You set up an Empowered Committee under Chairmanship of the West Bengal Finance Minister, Shri Asim Dasgupta. And, yet, after 2004, you started opposing it on the record. We then set up a second Empowered Committee. We appointed Shri Sushil Modi as the Chairman and yet the principle opposition came from the then Gujarat Chief Minister, the present hon. Prime Minister. It came from the Madhya Pradesh Chief Minister. There are many more examples. I remember the Tweet of the then Gujarat Chief Minister and present Prime Minister in December, 2012. He said, "Congress is giving the nation to foreigners. Most parties opposed the FDI, but with CBI, Congress got it through the backdoor." This is the kind of opposition to FDI. And the first thing the present Finance Minister starts with is, he is talking of 49 per cent in defence and 49 per cent in insurance.

जैसा कि गालिब ने कहा है इस प्रकार के आडम्बर के बारे में, दो पंक्तियां आपकी अनुमति से मैं कह रहा हूंः

'उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा,
धूल चेहरे पर थी और मैं आयना साफ करता रहा।'

Then the third issue is, of course, there are some good things or a lot of good things about the Budget. You have been told, imitation is the best form of flattery, in the other House; Gandhiji said, 'imitation is the sincerest flattery'. But it is better, I would submit, for the Government to fail in originality then to succeed in imitation. We know this, but it is important to remind ourselves and we are not bloated by the flattery. We treat it like chewingum. We enjoy it, but we do not swallow it. But it is important to remind this hon.

House that our revenue targets have been accepted in the Budget. The figures are there. Most importantly our three year fiscal roadmap has been accepted; 4.6 this year, 4.1 next year and 3.6 the third year. Now I am asking myself that if we have ruined the economy, if it is such a desperate state of a bankrupt nation which you have got in legacy, then by what arithmetic do you accept the figures of revenue, of deficit roadmap and so many others? Indeed, it shows that the present Budget is about as close a clone of the Interim Budget of February, 2014. So, at least, do not attack us on the one hand and copy and imitate us on the other. This Government has gone on a renaming spree. Renaming is good. But renaming doesn't add any solid physical assets. It is important not only to name or rename a child, but it is also important to give him sustenance to support and to nurture. Mere renaming shows a lack of creativity. Now we know about the names. The Skill Development Mission, for which we gave ₹1,000 crores, has now got the name 'Skill India'. The Accelerated Irrigation Benefits Programme, which was given ₹1,000 crores by us, is now grandly called 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana'. Then, the most important ones, the JNNURM and the Bharat Nirman, have become the Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission, and so on and so forth. We do not object to the *naamkaran* but we, certainly, object to the fact that there is no substance and no value addition.

Sir, within the limited time available, let me come to some of the aspects of the Budget itself. As I said, imitation continues to be a very good form of flattery, and you have to only turn to the Interim Budget prepared as recently as February, 2014. If you look at the figures, it is about as close a clone in many, many respects to the Budget which you have now presented. For example, there are 18 Flagship Schemes both in the Budget and earlier. Of these 18, I find that 11 have no change; there is zero change, neither a paisa nor a rupee change. Four more have minor changes of ₹ 200 crores to ₹ 250 crores. So, effectively, 15 have either zero change or negligible change. There are only two changes in Flagship Schemes. In one, that is, the Prime Minister Gram Sadak Yojana, you have increased it by ₹ 1,400 crores. In the other, the Accelerated Irrigation Benefits Programme, which you have renamed, you have, actually, decreased it by ₹ 1,800 crores. I am referring to figures from the Interim Budget and the current Budget. We find that for total receipts with borrowings, for net tax revenue, for total expenditure, for increase in non-Plan expenditure--these are vital parameters of a Budget -- the difference between the Interim Budget and the Budget presented now is one per cent or two per cent in some cases. There are identical figures on major parameters. The difference is one to two per cent. We, therefore, bow down before the imitation and flattery syndrome which you have exhibited. Now, the problem which I have with several parts of the Budget is that it has a very grandiose announcement and impressive statements, but no detail is given.

[डा. अभिषेक मनु सिंघवी]

There is no roadmap answering as Rudyard Kipling said, "There are six questions - how, what, when, why, where and in what manner." For example, a large part of the Budget is dependent on disinvestment. Disinvestment is to get you, according to your Budget Estimates, ₹ 58,000 crores. This is more than double the disinvestment figure in any prior Budget. And a large amount of your fiscal deficit calculation, your revenue collection, how you will keep your corpus full, is based on how you will get ₹ 58,000 crores. The last highest figure was half of this. But there is no explanation as to how they will get ₹ 58,000 crores. In fact, the statistics show that in the last 11 out of 14 years, 14 years include the NDA Government's *kaaryakaal* largely -- the disinvestment target, which was half of these, has not been met. Yet a centerpiece of your theory of getting tax revenues curbing the fiscal deficit, having growth, is getting Rs.58,000 crores on disinvestment but not telling the nation how and in what manner.

Then, just see some of the impossibilities. The GDP growth you have assumed nominally, with the money inflation, is at 13.4 per cent which your Budget assumes. That includes inflation, money value etc. Now we all know that we are somewhere between four to five per cent or five and a half per cent. How this validation of a GDP nominal growth of 13.4 per cent is to be realistically achieved when the current prognosis is somewhere just over one-third? I don't mind. With inflation you have not told us how nominal GDP of 13.4 per cent is? Are you assuming real of five and inflation of 8.4 per cent? Now, if you go further, it is very interesting, that your tax revenue which you assume is 18 per cent, *i.e.* five per cent higher than nominal GDP. If you see your Budget Speech, paragraphs 211 and 247, you also say that the tax proposals have a loss of ₹ 14,675 crores. On the one hand, you have tax proposals with net loss, on the other hand you have tax revenue expected by 18 per cent to rise. Your nominal GDP is to rise by 13 plus per cent. Can we expect some very superb tax compliance that the whole country -- crores of people -- starts putting tax in the coffers? Otherwise, you have not said how. Tax proposals have a loss of ₹ 14,000 crores and on the other hand you are having an 18 per cent tax revenue growth projected. My point is not the detail. My point is, let us not have too much jugglery, let us not have too many false promises, grand plans which are perhaps doomed to failure even when you state them because you have not told us how. Take, for example, a small thing but an interesting thing. You are saying that non-tax revenue will rise by ten per cent from the Revised Estimate to the Budget Estimate. Now, most of this is by tolls on roads and bridges. Now, either you will hike up the toll rate too much; otherwise, you cannot increase by ten per cent because you can't build so many new roads and bridges. So the problem is, the detail is missing. You are showing that you will decrease/increase subsidies only by two per cent and you know very well that the biggest subsidy is ₹ 22,000

crores on petroleum. But I don't find any explanation how you will curb that and yet your entire subsidy will increase by two per cent if your calculations are otherwise to hold good. A lot has been said about your ₹ 100 crore schemes. There are so many of them. The most curious I found was the one which said, 'Hundred crore programmes promoting good governance'. There can be no sentence more delightfully vague in what you are promising at ₹ 100 crores, programme promoting good governance is ₹ 100 crores. Of course, we have commented on the metro projects in Lucknow and Kanpur. What does a one kilometer or two kilometer line in Mumbai cost? A metro project, even for planning or conceptualization, even if you repeat ₹ 100 crores for five years, I don't know the meaning of metro projects in Lucknow and Kanpur for ₹ 100 crores. Archaeological site preservation- the number of archaeological sites notified under the Act by the ASI is ₹ 100 crores. It may not even come to a few hundred rupees per site or maybe a few thousand rupees per site. Is this tokenism? Most importantly, even if you put it for some and not all, does it have the synergy? The basic principle is that don't throw in so little that later on you will have to throw in much more to retrieve the bad money which you have thrown in because this has no synergy. How can you have both mortality and education of the girl child, *Beti Bachao, Beti Padhao*? That means both padhao and bachao, mortality and education is Rs. 100 crores. I am not making comparison with statues. Even by itself, is it 'ऊंट के मुंह में जीरा' ? Is it just to make a symbolic announcement? Is it just to please all? What is the meaning? There is no fleshing out. The real problem is no fleshing out. I could go on. My time is limited. I will say a couple of words and I will end. One thing I would have liked the hon. Finance Minister and the Government to have done is to have given a concrete roadmap on this. At least, consider giving specifics when 3 per cent of this country pays just under 70 per cent of all taxes collected. Sir, 3 per cent of taxpayers give you just under 70 per cent of taxes collected. I believe, if you were to add Rs. 1 lakh tax paid per year by 10 crore taxpayers in India, I refused to believe that Coimbattores, the Jhalandharis, the Ludhianvis, the Bellaries, the Kanpuris, the Punes, the Jaipurs do not have an aggregate of many crores who can give Rs. 1 lakh as tax every year. Imagine your tax collection. Instead of digging deep to expand from the 3 per cent base and all this talk, I have found no details as to how that expansion will takes place.

Friends, I will end as I began. It was not only a question of political campaign or hype and hoopla. It was a genuine mandate. It was a mandate for change. There is no doubt. It is the first sentence of the hon. Finance Minister's speech. Certainly, this Budget does not do justice to that mandate. Certainly, this Budget does not do justice to even mild expectation, but the expectations were much more than mild. And, therefore, I hope and trust that you will do much better next time, much, much better. Thank you.